



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229936
CG-DL-E-24092021-229936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021
मामला सं. (एडी-ओआई-21/2020)

विषय: चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेरॉक्सोसल्फेट (परसल्फेट) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/25/2020-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेरॉक्सोसल्फेट (परसल्फेट) (जिसे आगे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स यूआई वीआर प्रा. लि. और मैसर्स केलिबर केमिकल्स प्रा. लि. (जिन्हें आगे यहां "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र (जिसे आगे यहां "याचिका" भी कहा गया है) प्राप्त हुआ। आवेदकों ने आवेदन पत्र में निर्धारित सूचना प्रदान की है।

3. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्ति करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 06/25/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 सितंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या 06/25/2020-डीजीटीआर जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार 28 सितंबर, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना दें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध करें।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
 - (i) फुलिदा इंडस्ट्री कं. लि.
 - (ii) हेबेई जिहेंग ग्रुप कं. लि., चीन
 - (iii) शांक्सी बाओहुआ टेक्नोलॉजीस कं. लि., चीन
 - (iv) ड्राई क्लोरीन कारपो. (डीसीसी), चीन
 - (v) डेगुना एनिशिप्टर्स जीएमबीएच एंड कं. केजी, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - (vi) इंडस्ट्रियल केमिकल्स ग्रुप, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - (vii) ई.आई. डुपोंट नेमरस, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - (viii) एफएमसी कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
- छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी।
 - (i) गुजरात थेमिस बायोसिन लि.

- (ii) निकोल पिरामल इंडिया लि.
 - (iii) पदमा एजेंसीज
 - (iv) अरबिंदो फार्मा लि.
 - (v) अरटेक सरफिन केमिकल्स लि.
 - (vi) नोवार्टिस इंडिया लि.
 - (vii) जेडेक्स इंडस्ट्रीज
 - (viii) वीनस इंसुलेटर्स प्रा. लि.
- झ. प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- (i) मैसर्स जय केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
 - (ii) मैसर्स रश्मि ट्रेडिंग कंपनी
 - (iii) मैसर्स सागर स्पेशियलिटी केमिकल्स प्रा. लि.
 - (iv) मैसर्स केम इंटेल्
- ञ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से वास्तविक गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण पहुंच योग्य नहीं थी।
- ट. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. प्राधिकारी ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त किये और लेनदेनों की उचित जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- ड. घरेलू उद्योग और उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- ढ. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे यहां "एनआईपी" भी कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 01 जून, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई है, अनुरोध दायर करें। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उनके खंडन पेश करने की सलाह दी गई थी।

- त. जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्क और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- थ. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 01.09.2021 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 07.09.2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट किया, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है, जहां तक संभव हो, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/ दस्तावेजों का संगत मानी गई सीमा तक सत्यापन किया।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- न. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किया है।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में "****" गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.24 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- जब पीपीएस के कोई आयात नहीं हैं, तो विचाराधीन उत्पाद की यह आवश्यकता कि उत्पाद को संबद्ध देशों के मूल से अथवा वहां से निर्यातित होना चाहिए, पूरी नहीं की जाती है। जांच की अवधि के दौरान भारत में आयात न किए गए उत्पाद किस्म को विचाराधीन उत्पाद से अलग किया जाना आवश्यक है।
 - उत्पाद की किस्म-वार पहचान अथवा पीसीएन सिद्धांत केवल तभी तैयार किया जाता है जब परस्पर किस्मों के बीच लागत और कीमत में काफी अंतर दर्शाया जाए और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि इस प्रकार पहचान की गई उत्पाद किस्म जिसका आयात नहीं किया गया था, विचाराधीन उत्पाद में फिर भी शामिल की गई हो।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- विचाराधीन उत्पाद 'पेरोक्सोसल्फेट्स' है, जिसे सामान्यतः 'परसल्फेट्स' के रूप में जाना जाता है। परसल्फेट्स निकट रूप से संबद्ध सम्मिश्रणों का समूह है। ये अल्काली मेटल साल्ट के रूप में उत्पादित किये जाते हैं जिनमें अमोनियम परसल्फेट्स (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट्स (पीपीएस) और सोडियम परसल्फेट्स (एसपीएस) शामिल होते हैं।

- (ii) उपर्युक्त तीनों किस्मों के परसल्फेट्स का रासायनिक सूत्र क्रमशः $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ है। तीनों किस्मों के परसल्फेट्स के वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में आरंभिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में समान अंतिम प्रयोग है। ये तीनों साल्ट एक और समान उत्पाद हैं जिसमें 'सफेद क्रिस्टलीन पाउडर' की दिखावट, पानी में घुलनशील, धीरे-धीरे डिकम्पोज होता है और नमी को सोखते समय ऑक्सीजन छोड़ता है।
- (iii) तीनों किस्मों के परसल्फेट एक ही सामान्य प्रयोजन का कार्य करते हैं। उपभोक्ता सामान्यतः कम समय में एक किस्म से दूसरी किस्म में नहीं जाते। ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जिनमें इन तीनों परसल्फेट का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा सकता है।
- (iv) संबद्ध देशों में उत्पादक तीनों किस्मों के परसल्फेट का उत्पादन परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और एक किस्म के परसल्फेट के पाटन से दूसरे किस्म के परसल्फेट के पाटन में आसानी से जा सकते हैं।
- (v) परसल्फेट्स उप शीर्ष 2833 40 और 283340 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 में वर्गीकृत है। तथापि, उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं, और वे जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- (vi) ए पी एस, पी पी एस और एस पी एस संबद्ध सामानों के भाग हैं और आयात प्रयोजनों के लिए अलग से नहीं देखे जा सकते। प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में भी इन तीनों ग्रेडों को एक उत्पाद माना है।
- (vii) आयातकों/प्रयोक्ताओं का यह तर्क कि पीपीएस का कोई आयात नहीं है, किसी तथ्यात्मक आधार के बिना है। जांच की अवधि के दौरान पीपीएस का किसी तरह से आयात होना नहीं माना जाना चाहिए और इस प्रकार उत्पाद किस्म को अलग करने के लिए आधार नहीं हो सकता।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 'पेरोक्सोसल्फेट्स' है, जिसे सामान्यतः 'परसल्फेट्स' के रूप में जाना जाता है। परसल्फेट्स निकट रूप से संबद्ध सम्मिश्रणों का समूह है। ये अल्काली मेटल साल्ट के रूप में उत्पादित किये जाते हैं जिनमें अमोनियम परसल्फेट्स (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट्स (पीपीएस) और सोडियम परसल्फेट्स (एसपीएस) शामिल होते हैं। इन परसल्फेट्स के रासायनिक सूत्र क्रमशः $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ हैं। तीनों किस्मों के परसल्फेट्स के वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में आरंभिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में समान अंतिम प्रयोग हैं और एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। ये तीनों साल्ट एक ही उत्पाद के विभिन्न रूप हैं।
8. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के इन तीनों रूपों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया है और चीन से परसल्फेट्स के आयातों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई जांचों पर भी विश्वास किया है, जिनमें परसल्फेट के इन तीनों रूपों को एक ही "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में माना गया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी पूर्व जांचों में परसल्फेट के तीनों रूपों को एक विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की लागत और कीमत में अंतर को ध्यान में रखते हुए पृथक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जांच की अवधि में पीपीएस का आयात नहीं किया गया है और इस प्रकार उसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एपीएस, एसपीएस और पीपीएस की उत्पादन प्रक्रिया की वैकल्पिकता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षति की अवधि के दौरान पीपीएस के आयात हैं, प्राधिकारी पीपीएस को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना उपयुक्त पाते हैं।
9. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों और आयातित उत्पाद में कोई अंतर होने का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

10. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों की "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग एवं आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आवेदक वीआर परसल्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड अब यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड है। इस प्रकार असंगतता के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
 - यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड अब यूनाइटेड इनिशिएटर्स जीएमबीएच (यूआई) के साथ संयुक्त उद्यम है। यूआई के साथ कंपनी का संबंध चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों के साथ यूआई वीआर के संबंध की जांच आवश्यक बनाता है क्योंकि यूआई का चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध उत्पादक/निर्यातक है।
 - याचिकाकर्ता ने यह तथ्य प्रकट नहीं किया कि यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड जर्मन मेजर, यूनाइटेड इनिशिएटर्स जीएमबीएच (यूआई) के साथ 2018 में एक एक संयुक्त उद्यम बना, और भ्रामक दावे कर रहा था कि ये कंपनियां एमएसएमई आदि हैं।
 - प्राधिकारी से आग्रह है कि वे यह जांच करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करें कि क्या संबद्ध सामानों का कोई आयात संबद्ध पक्षकार से था। इसके अतिरिक्त, यूआई वीआर प्रा. लिमिटेड को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे यूआई वीआर की किसी भी संबद्ध कंपनी से संबद्ध सामानों के किसी निर्यात के ब्यौरों सहित उन पक्षकारों के साथ अपने संबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण दें।
 - यूआई के साथ अपने संबंध को प्रकट करने में कंपनी की विफलता यह दर्शाती है कि घोषणा विश्वसनीय नहीं है, और ऐसे संबंधों की पूरी जांच अनिवार्य है। इस सीमा तक, संबंधित याचिकाकर्ता कंपनी का आधार घरेलू उद्योग के रूप में विवादास्पद है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- यह आवेदन पत्र मैसर्स यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कैलिबर केमिकल्स प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं।
 - आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है और इस प्रकार वे नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं तथा आवेदन पत्र नियमावली के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - वीआर परसल्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 50 प्रतिशत दावा लेकर यूनाइटेड इनिशिएटर्स (यूआई) नामक जर्मन कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया और परिणामस्वरूप, कंपनी का नाम बदलकर वीआर परसल्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड से यूआई-वीआर प्राइवेट लिमिटेड कराया। परिवर्तित नाम कंपनी के पत्र शीर्ष में उल्लिखित था और यह सूचना सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध थी।
 - संयुक्त उद्यम का प्रभाव इस जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक कंपनी की कानूनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया, क्योंकि कंपनी अब भी उसी तरह भारत में निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं है। कंपनी पूर्व जांचों की तरह ही है और अब भी भारत में परसल्फेट्स की एक प्रमुख विनिर्माता है।
 - प्रयोक्ता/आयातक द्वारा दिया गया यह विवरण कि आवेदक कंपनी का पत्र शीर्ष पूरी तरह से कमी वाला तर्क नहीं माना जा सकता, पत्र शीर्ष आवेदक कंपनी का परिवर्तित नाम है, जिसके संबंध में आयातकों/प्रयोक्ताओं ने भी आरोप लगाया है और स्वीकार किया है। केवल इस कारण कि कंपनी का पूर्व नाम जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आवेदक ने कोई तथ्य छिपाए हैं।

- (vi) केवल नजर से छूट जाने के कारण त्रुटि थी, जब आवेदक ने पूर्व याचिका से विषय-वस्तु के भाग की नकल की। तथापि, यह किसी तरह से वर्तमान कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता।
- (vii) आवेदक ने प्राधिकारी से कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यह यूआई-वीआर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में आवेदक के नाम वाले पत्र शीर्ष से सिद्ध है, जिसका प्रयोग आवेदक द्वारा ई-मेल के माध्यम से अधिकारियों द्वारा पूछी गई बातों के उत्तर में जांच से पूर्व विभिन्न अवसरों पर प्रयोग किया गया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दायर विभिन्न सूचनाओं को पहले ही सत्यापित किया है।
- (viii) आवेदकों ने प्राधिकारी से कभी भी कोई तथ्य नहीं छिपाया है और प्राधिकारी ऐसी कोई भी अधिसूचना/शुद्धिपत्र जारी कर सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें। तथापि, घरेलू उद्योग मानता है कि किसी शुद्धिपत्र का आवश्यकता नहीं है।
- (ix) संयुक्त उद्यम का यूआई वीआर के संबंध संबंधी मानदंडों पर कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार, यह आवेदक कंपनी की पात्रता को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त उद्यम के बाद, आवेदक कंपनी जर्मन कंपनी की किसी संबद्ध कंपनी से संबद्ध नहीं है। आयातक/प्रयोक्ता द्वारा उल्लिखित कोई भी पक्षकार यूआई वीआर से संबद्ध नहीं है और आवेदक कंपनी किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं है। इस प्रकार, यूआई वीआर नियमावली के सभी मानदंडों को पूरा करती है और एक पात्र घरेलू उद्योग है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. यह आवेदन पत्र मैसर्स यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कैलिबर केमिकल्स प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक अर्थात् मैसर्स गुजरात परसाल्ट प्रा. लिमिटेड और योयो केमिकल्स हैं। आवेदकों का भारत में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन में 96 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और भारत में किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वीआर परसल्फेट और एक जर्मन मेजर अर्थात्, यूनाइटेड इनिशिएटर्स जीएमबीएच (यूआई) के विलय के तथ्य को छुपाया है और अब कंपनी का नाम यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है। घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख करते हुए उत्तर दिया कि यह तथ्य सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराया गया था और उनकी ओर से यह गलती से त्रुटि थी कि उन्होंने आवेदन पत्र में आवेदक का नाम नहीं बदला तथा पुराने नाम पर चलते रहे। तथापि, यूआई वीआर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर प्राधिकार पत्र में कंपनी का नया नाम निहित था और वह सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया था।
15. यह नोट किया जाता है कि वी आर परसल्फेट ने जर्मन कंपनी यूनाइटेड इनिशिएटर्स जीएमबीएच (यूआई) के साथ 50% संयुक्त उद्यम में करार किया। विलय के बाद, यूनाइटेड इनिशिएटर का वी आर परसल्फेट में 50% हिस्सा है। चीन अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में यूआई से संबंधित कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार, संयुक्त उद्यम नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए आवेदक कंपनी की पात्रता को भंग नहीं करता।
16. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता के मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर पूर्णतः कमीयुक्त हैं और गोपनीयता के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।
- (ii) किसी भी आयातक ने निर्धारित तरीके से उत्तर का अगोपनीय रूपांतर दायर नहीं किया है और सभी उत्तर दिनांक 07.09.2020 की व्यापार सूचना 10/2018 की पूर्णतः अवहेलना करते हुए हैं, जिससे उनके द्वारा दायर सूचना पर कोई सार्थक टिप्पणी करने में घरेलू उद्योग असमर्थ है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

20. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने ई-मेल के परिचालन के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

सामान्य मूल्य

21. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें निम्नलिखित रूप में हल किया है:
- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में पाटन मार्जिन के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे कठोर जांच के अधीन रखे जाने चाहिए क्योंकि पूरा दावा इस तथ्य को प्रकट किए बिना किया गया है कि यूआई वीआर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संबद्ध पक्षकार को संबद्ध सामानों का काफी निर्यात किया है और माने गये सामान्य मूल्य में स्पष्ट रूप से संबद्ध पक्षकार के लेनदेन शामिल हैं जो आज की तारीख तक प्राधिकारी को प्रकट नहीं किए गए हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. जांच प्रक्रिया के दौरान एमईटी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न सामान्य अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका में खपत मूल्य के संबंध में आवेदकों द्वारा पर्याप्त साक्ष्य और विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। चूंकि देश में आयात संबद्ध देश के भीतर खपत के लिए होते हैं, अतः देश में खपत के लिए निर्धारित सामानों की कीमत के संबंध में उसकी कीमत निरपवाद रूप से सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में कार्य कर सकती है।
- (ii) संबद्ध देश में संबद्ध सामानों की खपत कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य हमेशा निर्मित सामान्य मूल्य से उच्च स्तर पर होना चाहिए।
- (iii) विगत जांचों पर विश्वास किया गया था, जिनमें प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ-साथ अंतिम जांच परिणाम के स्तर पर संबद्ध देशों में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया था और साथ ही "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य [फा. सं. 6/3/2019-डीजीटीआर] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्मिश्रण में प्रसंस्कृत अथवा अप्रसंस्कृत, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में भी विश्वास किया गया था।
- (iv) ओसीटी परीक्षण का परिणाम सामान्य मूल्य को करना नहीं है बल्कि सामान्य मूल्य बढ़ाना है। अतः, किसी भी दशा में, आयातक (अथवा निर्यातक) को इस निमित्त कोई आपत्ति नहीं हो सकती और सिद्धांत की अनुपयुक्तता का तर्क नहीं दे सकते। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर सामान्य मूल्य को अपनाने का तर्क दिया है और इसलिए, यह तथ्य कि प्राधिकारी ओसीटी परीक्षण लागू करने में सक्षम नहीं हो सकते, इस प्रयोजन के लिए पूर्णतः असंगत है।
- (v) प्राधिकारी के लिए अमेरिका में उत्पादक की कारखानागत कीमत निर्धारित करना अपेक्षित है न कि भारत में उत्पादक की कारखानागत कीमत। क्षति मार्जिन निर्धारित के लिए लागू किया गया सिद्धांत इस संबंध में संगत है। यदि प्राधिकारी पत्तन पर आयातों की पहुंच कीमत कारखानागत क्षतिरहित कीमत का पर्यायवाची मानते हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि अमेरिकी बंदरगाह पर कीमत अमेरिकी उत्पादक की कारखानागत कीमत का पर्यायवाची है।

- (vi) यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत एक संबंधित पक्षकार के लिए है और अविश्वसनीय है, का कोई आधार नहीं है। अमेरिकी पक्षकार ने इस उत्पाद को उस कीमत से 10% अधिक कीमत पर बेचा जिस कीमत पर उसने सामग्री खरीदी। इस प्रकार, यदि अमेरिकी उत्पादक के वास्तविक बिक्री मूल्य पर विचार किया जाए, तो यह देखा जाएगा कि यह सामान्य मूल्य में और वृद्धि करेगा।
- (vii) आवेदकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध कंपनी की पहुंच कीमत की गणना प्रस्तुत की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य को उस कीमत के रूप में माना जाएगा जिस पर अमेरिकी बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की जा रही है। सामान्य मूल्य के लिए कीमत को खपत कीमत के रूप में लिया जाएगा, न कि उस कीमत पर जिस पर आवेदक कंपनी द्वारा उसकी संबद्ध कंपनी को बेचा गया था। संबद्ध कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में यथावत रूप से संबद्ध सामानों बिक्री नहीं करेगी, बल्कि अपना मार्जिन भी शामिल करेगी।
- (viii) घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि भारत से निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर हैं जिस पर अमेरिकी उत्पादक अपनी घरेलू कीमतों में उत्पाद की बिक्री कर रहा है। इसलिए, सामान्य मूल्य को आयात कीमत (सभी समायोजनों के बाद) और उस मार्जिन के रूप में माना जाना चाहिए जिसके द्वारा अमेरिकी उत्पादक अपने घरेलू बाजार में उच्च कीमत पर उत्पाद बेच रहा है। अमेरिका में खपत मूल्य निर्धारित करने के लिए मार्जिन को और जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक संयुक्त राज्य अमेरिका को उस कीमत की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहा है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को निर्यात कर रहा है।
- (ix) जिस बिक्री कीमत पर यूआई वीआर प्रा. लि. संबद्ध पक्षकार को बिक्री करता है, वह आस-पास की है, और निर्यातक तथा आयातक के बीच लेन-देन संबंध के कारण अप्रभावित हैं।
- (x) तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा सूचित की गई वास्तविक बीजक कीमत दो कारणों से निर्मित सामान्य मूल्य से साक्ष्य की मात्रा से अधिक है - (क) नियम में बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत के बीच स्पष्ट अनुक्रम का प्रावधान है, (ख) जबकि बिक्री मूल्य अमेरिकी निर्माता की कीमत के लिए प्रतिनिधिकारक है, उत्पादन लागत अमेरिकी उत्पादक की लागत के लिए प्रतिनिधिकारक है। इस प्रकार, किसी भी दशा में, इस सूचना की अनदेखी नहीं की जा सकती।
- (xi) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से नियमित रूप से ट्रेड जर्नल कीमतें अपनायी हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने वास्तविक खरीद मूल्य के संबंध में सूचना प्रदान की है और यह सूचना निर्यात की महत्वपूर्ण मात्रा से संबंधित है जो भारत में आयात को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है।
- (xii) आवेदकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध कंपनी की पहुंच कीमत की गणना प्रस्तुत की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य को उस कीमत के रूप में माना जाएगा जिस पर अमेरिकी बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की जा रही है। सामान्य मूल्य के लिए कीमत को खपत कीमत के रूप में लिया जाएगा, न कि उस कीमत पर जिस पर आवेदक कंपनी द्वारा उसकी संबद्ध कंपनी को बेचा गया था। संबद्ध कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में यथावत रूप से संबद्ध सामानों बिक्री नहीं करेगी, बल्कि अपना मार्जिन भी शामिल करेगी।
- (xiii) किसी भी निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है और इस प्रकार यह विवाद नहीं किया है कि संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है और इस पर भी आयातकों की सीमित प्रतिभागिता द्वारा विवाद नहीं किया गया था।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

24. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

25. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है।
26. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है और निर्यातक प्रश्नावली दायर नहीं की है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

I. चीन जन. गण.

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माने गए किसी देश के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार परकलित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, चीन

जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) की प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसीलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत विकल्पों का पता लगाए जाने की आवश्यकता है। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अथवा जहां वह संभव न हो, उस तीसरे देश से अन्य देश में कीमत, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त कीमत अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-7 के तहत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। आवेदकों ने अनुरोध किया था कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर शुल्क लगाए हैं और यूरोपीय आयोग ने हाल ही में दिनांक 16 जनवरी, 2020 को चीन से परसल्फेट के आयातों के विरुद्ध की गई निर्णायक समीक्षा जांच में चीन के लिए टर्की को उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना है। यह नोट किया जाता है कि टर्की से भारत को भी संबद्ध सामानों का काफी निर्यात है। आवेदकों ने (क) टर्की में संबद्ध सामानों के आयात और (ख) भारत सहित तीसरे देश को संबद्ध सामानों के निर्यातों के संबंध में सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, टर्की से भारत को निर्यातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि यह मात्रा काफी है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार मानी जा सकती है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने टर्की को उपयुक्त तीसरा देश माना है और भारत में टर्की की औसत निर्यात कीमत सामान्य मूल्य के रूप में मानी गई है। निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

II. संयुक्त राज्य अमेरिका

ख. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

28. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातें आधार बन सकती हैं।
- क. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत,
 - ख. निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनात्मक प्रतिनिधिकारक कीमत,
 - ग. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ-साथ मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।
29. कानून के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी को उस समय उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करने की आवश्यकता होती है जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू बाजार में खपत के लिए हो। आवेदकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी संबंधित कंपनी द्वारा, जिससे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया गया था, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संबद्ध वस्तुओं की पुनर्विक्रय कीमत भी उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की पुनर्विक्रय कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं की औसत आयात कीमत के साथ तुलनीय है जैसा कि विश्व व्यापार आंकड़ों से देखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी तीन प्रकार की संबद्ध वस्तुओं के लिए 10 अंकों के स्तर पर एक समर्पित एचएस कोड है। घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य का निर्धारण संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमत का उपयोग करते हुए, उचित समायोजन करने के बाद किया गया है, और ऐसी कीमत को यूएसए के लिए सामान्य मूल्य माना गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित स्वरूप और तरीके में प्राधिकारी को वह सूचना नहीं दी है जिसका प्रयोग निर्यात कीमत और अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सके। अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के

लेनदेन वार आंकड़ों के आधार पर किया है। कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के निमित्त समायोजित किया गया है। भारत को पृथक भारित औसत निर्यात कीमत प्रत्येक किस्म के परसल्फेट के लिए निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाये गये अनुसार निर्धारित की गई है।

च.4 पाटन मार्जिन

31. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। चूंकि जांच की अवधि में पीपीएस का कोई निर्यात नहीं हुआ है, इसलिए इसके लिए पाटन मार्जिन की गणना नहीं की गई है। संबद्ध देशों से आयातों का पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक ही नहीं है, बल्कि काफी भी है।

पाटन मार्जिन तालिका

देश : संयुक्त राज्य अमेरिका

विवरण	एपीएस	एसपीएस	औसत
	अमे. डॉ./मी. टन		अमे. डॉ./मी. टन
सामान्य मूल्य	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***	***
पाटन मार्जिन	***	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***	***
पाटन मार्जिन % (रेंज)	130-140	60-70	80-90
आयात मात्रा (मी. टन)	429	578	1,007

देश : चीन

विवरण	एपीएस	एसपीएस	औसत
	अमे. डॉ./मी. टन		अमे. डॉ./मी. टन
सामान्य मूल्य	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***	***
पाटन मार्जिन	***	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***	***
पाटन मार्जिन% (रेंज)	60-70	10-20	60-70
आयात मात्रा (मी. टन)	1,649	60	1,709

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन**क्षति निर्धारण के लिए सिद्धांत और कारणात्मक संपर्क की जांच**

32. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (i) याचिकाकर्ताओं का यह खंडन कि क्षति संबंधी प्रपत्र संचयी आधार पर दिए गए थे, जिसका अर्थ संचयी मूल्यांकन के लिए मांग है, क्योंकि संचयी मूल्यांकन के लिए दावा समुचित आधारों का उल्लेख कर औचित्यपूर्ण किया जाना चाहिए और क्षति के लिए संयुक्त प्रपत्र प्राप्त करना ही अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा।
 - (ii) याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संचयी मूल्यांकन का औचित्य बनाने के लिए कोई स्पष्ट दावे नहीं किये।
 - (iii) आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाधीन उत्पाद की कीमत चीन जन. गण. की तुलना में 50.88% तक अधिक थी और चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में 69.71% तक अधिक थी। चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से कीमत और मात्रा में अंतर काफी है। चीन जनवादी गणराज्य से आयात कीमत और मात्रा यह दर्शाती है कि दावा की गई क्षति उन आयातों के कारण हो सकती है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका से उचित एवं अधिक कीमत वाले आयात कारण नहीं होना चाहिए।
 - (iv) चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से मात्रा और पहुँच कीमत की तुलना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि ये दोनों भिन्न दिशाओं में गए और उसके बाद दोनों को संचित करना तर्कहीन है।
 - (v) संयुक्त राज्य अमेरिका से एपीएस का आयात नकारात्मक कटौती स्तर पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जन. गण. से एसपीएस में कटौती के बीच भारी अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद पर कटौती में भी काफी अंतर है।
 - (vi) आयातकों ने अंतिम प्रयोक्ता स्तर पर गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण चीन जन. गण. की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की सामग्री और भारतीय उत्पाद को प्राथमिकता दी तथा कीमत के बारे में कोई चिंता नहीं थी। संबद्ध देशों के आयातों की प्रतिस्पर्धी की स्थितियाँ और घरेलू बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों और अन्य उत्पादों के लिए समान नहीं थीं।
 - (vii) चीन जन. गण. से आयात वर्तमान जांच की अवधि के दौरान कीमत में तेजी से गिरावट से शुल्क की समाप्ति के बाद काफी बढ़े, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों में 2018-19 की अवधि में जांच की अवधि में लगभग 307 मी. टन तक गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान कीमत स्पष्ट रूप से पूर्व वर्षों से तुलनीय थी। इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों को एक ही धरातल पर नहीं रखा जाना चाहिए।
 - (viii) संबद्ध देशों के लिए पृथक रूप से पाटन और क्षति की जांच से किसी भी तरीके से याचिकाकर्ताओं के वैध हित प्रभावित नहीं होंगे।

- (ix) याचिकाकर्ताओं का यह स्वीकार करना कि वे एक जवाबी उपाय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान कीमत से कम कीमत पर संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध सामानों का निर्यात कर संयुक्त राज्य अमेरिकी बाजार में कीमत कटौती कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विदेशी बाजारों में विस्तार करने के लिए ऐसे परिपाटियां लगाने के लिए भारतीय बाजार में शुल्क चाहता है जो पाटनरोधी शुल्क जांच प्रयोजन नहीं है। यह तथ्य है कि याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में इन व्यापार परिपाटियों में लगने में सक्षम हैं, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया पाटन और क्षति का दावा केवल अन्य विस्तारवादी प्रयोजनों के लिए पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग करने के लिए है।
- (x) तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के आयात के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई।
- (xi) शुल्क की समामि के बाद आयात चीन जन. गण. से काफी बड़े और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों में काफी गिरावट आई जो याचिकाकर्ता के इस दावे को समाम करना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर शुल्क की समामि संयुक्त राज्य अमेरिका से निरंतर आयातों का एक कारण रही है।
- (xii) जांच की अवधि के दौरान लाभ और आरओसीई में गिरावट याचिकाकर्ताओं की ब्याज एवं मूल्यहास लागतों में काफी वृद्धि के कारण है और लाभ में गिरावट संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों से नहीं जोड़ी जा सकती। लागत में यह वृद्धि जांच की अवधि के दौरान और तत्काल पूर्व वर्ष के दौरान भी नई क्षमता अभिवृद्धियों के कारण है।
- (xiii) कंपनी का नकद लाभ जांच की अवधि में 100 से 106 अंक तक बढ़ा जो घरेलू उद्योग की अच्छी स्थिति दर्शाता है और जो यह भी दर्शाता है कि लाभ में दावा की गई गिरावट लागत में वृद्धि के कारण ही रही है।
- (xiv) बहु-विध क्षमता अभिवृद्धियों के बाद भी उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर थे।
- (xv) घरेलू उद्योग सभी मोर्चों पर अपने व्यापार का विस्तार कर रहा है जो कि क्षमता में वृद्धि और लाभप्रदता मानदंडों संबंधी बहुत सुदृढ़ निष्पादन से युक्त निर्यातों से सिद्ध है।
- (xvi) दावा की गई क्षति और संयुक्त राज्य अमेरिका से तथाकथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- (xvii) यूआई वीआर परसल्फेट्स द्वारा विनिर्मित तीनों सामग्रियों (एपीएस, एसपीएस और पीपीएस) का वास्तव में बहुत छोटा जीवनकाल है, जो स्टॉक करते समय भारी गुणवत्ता परिवर्तनों में रहता है।
- (xviii) उच्च गुणवत्ता के कारण, आयातक स्थानीय रूप से विनिर्मित सामानों में संयुक्त राज्य अमेरिकी आयातों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके उपभोक्ताओं को अपने प्रसंस्करण में स्थानीय रूप से विनिर्मित सामग्री की अपेक्षा आयातित सामग्री की कम मात्रा का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।
- (xix) याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि यूआई की चीन जन. गण. में काफी उत्पादन सुविधाएं हैं और कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को आयात रोकने के लिए भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी पाटनरोधी शुल्क लगवाना चाहती है।
- (xx) क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय नए निवेश पर 22% आरओसीई नहीं माना जाना चाहिए, और अनुचित एनआईपी तथा आय स्तरों से बचने के लिए ऐसे नए निवेशों के मामले में उपयुक्त विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) आवेदन पत्र में प्रस्तुत आंकड़ों के सभी मानदंड और कारक संचयी रूप से स्पष्ट किए गए थे जिसका अभिप्राय यह था कि संबद्ध देशों से आयात और उनका प्रभाव संचयी रूप से हल कर दिया गया है।

- (ii) आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों का विश्लेषण देने की आवश्यकता नहीं है, और आवेदन पत्र के समर्थन में केवल आंकड़े प्रदान करना ही पर्याप्त है। इस विचार की चर्चा मेक्सिको - कॉर्न सिरप और थाईलैंड - एच-बीम्स में पैनल द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई नियम नहीं है कि घरेलू उद्योग को प्रत्येक दावा लिखित में करना चाहिए।
- (iii) अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि यह मामला संचयी निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि चीन की आयात मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है और चीन की आयात कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका से कम है, भ्रामक है क्योंकि वह भारत औसत कीमत तुलना के आधार पर है।
- (iv) चीनी और अमेरिकी एसपीएस के बीच कीमत अंतर काफी नहीं है, जबकि एपीएस में काफी कीमत अंतर है। आयात मात्राएं चीनी कीमतें अमेरिका की कीमतों से कम होने के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिकी की तुलना में चीन से काफी बड़ी हैं।
- (v) हितबद्ध पक्षकारों ने पुष्टि की कि उनका संबंध केवल एसपीएस से था और इसलिए, एपीएस में चीनी और अमेरिकी उत्पाद के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के संबंध में प्राधिकारी की सहायता नहीं कर सकते। अमेरिका और चीन के बीच कीमत अंतर में हाल की अवधि में काफी गिरावट आई है और इस प्रकार वह परस्पर प्रतिस्पर्धा दर्शा रहा है।
- (vi) अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से मात्रा और पहुंच कीमत भिन्न दिशाओं में नहीं गई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिकी विनिर्माता पेरोक्सीकेम ***/पीएमटी की सीआईएफ कीमत पर एसपीएस का निर्यात कर रहा है जबकि चीनी विनिर्माता उसी ग्रेड का निर्यात सीआईएफ कीमत **** डॉलर/पीएमटी की पर कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भार लागत चीन से तीन गुना अर्थात् 2500/पीएमटी है, जबकि चीन से भाड़ा लागत *** डॉलर है। इस प्रकार, प्रभावी रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से कारखानागत कीमत चीन से काफी कम है, जबकि पहुंच कीमत काफी तुलनीय है। इसका सत्यापन आयातकों से भी किया जा सकता है।
- (vii) घरेलू उद्योग ने उनके पीपीएस के निष्पादन में बहुत कम अथवा कोई ह्रास नहीं हुआ था क्योंकि पीपीएस के कोई आयात नहीं थे, परंतु एपीएस और एसपीएस के काफी आयातों के कारण एपीएस और एसपीएस में घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी गिरावट थी। परिणामस्वरूप, एपीएस की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई और एसपीएस की लाभप्रदता नकारात्मक हुई।
- (viii) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना संबद्ध देशों में क्षमताओं की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि करती है, और वे भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात काफी पाटित कीमत पर कर रहे हैं।
- (ix) यहां तक कि जब घरेलू उद्योग इष्टतम से कम कीमतें पेश कर रहा है, तो उसका बाजार हिस्सा स्थिर है और वस्तुतः जांच की अवधि में उसमें थोड़ी गिरावट आई है, जबकि संबद्ध सामानों के लिए मांग में काफी वृद्धि हुई है।
- (x) संबद्ध देशों से आयातों में 2017-18 तक वृद्धि हुई और 2018-19 में थोड़ी सी गिरावट आई, यह संभवतः इसलिए है क्योंकि निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के संबंध में मालूम था। यह पुनः जांच की अवधि में काफी बड़े जो पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने का प्रभाव दर्शाता है।
- (xi) संबद्ध सामानों के लिए मांग 2017-18 तक बढ़ी और 2018-19 में उसमें गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में बढ़ी। आवेदकों ने मांग में वृद्धि के अनुरूप क्षमता बढ़ाई। तथापि, आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक थी।
- (xii) बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार, आयातों से जांच की अवधि में घरेलू कीमत पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।
- (xiii) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। संबद्ध सामानों की समग्र रूप से तथा प्रत्येक संबद्ध देश से एपीएस और एसपीएस के लिए कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

- (xiv) दोनों संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क बंद होने के बाद आयातों में काफी वृद्धि हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात उस समय भी हमेशा काफी रहे जब शुल्क लागू था। इस भारी क्षमता, बहुत अधिक घरेलू कीमतों और बहुत ही सस्ती दर पर विद्युत की उपलब्धता से, संयुक्त राज्य अमेरिका पाटनरोधी शुल्क खपाने में सक्षम था और क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात जारी रखा।
- (xv) संयुक्त राज्य अमेरिका संबद्ध सामानों का निर्यात निरंतर करने में सक्षम रहा क्योंकि वे पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद भी घरेलू कीमत में हमेशा और निरंतर कटौती कर रहे थे। इस प्रकार, आयातकों का यह कहना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों को गुणवत्ता के कारण प्राथमिकता दी जाती है, एक धोखा है।
- (xvi) संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनुचित कीमत पर अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, परंतु इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चीन की तरह काफी क्षमताएं हैं, और दोनों देश पाटित कीमतों पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं।
- (xvii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 में गिरावट आई और उसके बाद 2018-19 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट आई, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।
- (xviii) घरेलू उद्योग बिक्री कीमतों से समझौता करने के बावजूद बाजार में पाटित आयातों की काफी मात्रा की मौजूदगी के कारण अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।
- (xix) संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में पूरी क्षति अवधि में काफी वृद्धि हुई। दूसरे देशों के बाजार हिस्से से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध देशों ने बाजार से अन्य उचित कीमत वाले सभी आयातों को समाप्त कर दिया है और अब भारतीय ग्राहक संबद्ध देशों से पाटित आयातों की दया पर हैं।
- (xx) घरेलू उद्योग की मालसूची में 2018-19 में और फिर जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई और इस प्रकार घरेलू उद्योग की सुभेद्यता दर्शाते हैं।
- (xxi) एपीएस और एसपीएस दोनों के लाभ में जांच की अवधि में भारी गिरावट आई, और पीपीएस के लाभ में 2017-18 में गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई क्योंकि जांच की अवधि में पीपीएस के कोई आयात नहीं थे। यह आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के बीच सीधा संपर्क दर्शाता है।
- (xxii) घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है और वह आयात कीमतों के साथ अपनी कीमतें रखने के लिए मजबूर था जिसमें वर्तमान जांच की अवधि में गिरावट आई।
- (xxiii) संबद्ध देशों से आयात कीमतों में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत न बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ।
- (xxiv) ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि पाटित आयातों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क नहीं तोड़ता।
- (xxv) लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय जैसे कीमत मानदंडों में वृद्धि नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है।
- (xxvi) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है।
- (xxvii) सभी सूचीबद्ध कारकों और किन्हीं अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन किया जाए। इसका ईसी-बेड लिनन में पैनल द्वारा भी उल्लेख किया गया था, जिसमें यह उल्लेख था कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक क्षति कारक, अलग-अलग क्षति का संकेतक होना चाहिए। इस प्रकार, कुछ मानदंडों में वृद्धि अलग से नहीं देखी जानी चाहिए।

- (xxviii) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध सामानों के निर्यात 1997 और 2007 से क्रमशः अमेरिका और यूरोपीय संघ में पाटनरोधी शुल्कों के अधीन रहे हैं। यूएसआईटीसी ने चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों पर 119% का जारी रखने का अगस्त, 2019 में अंतिम निर्धारण अपनी चौथी शीघ्र समीक्षा में जारी किया। यूरोपीय आयोग ने भी दिनांक 16 जनवरी, 2020 की हाल के निष्कर्ष की अपनी समाप्ति समीक्षा में 24 - 71.8% की रेंज में चीनी आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय आयोग ने भी चीनी निर्यातक के विरुद्ध प्रवंचनारोधी जांच शुरू की।
- (xxix) अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में विद्यमान कीमतें भारत में विद्यमान कीमतों से 50-100% अधिक हैं। यह महज एक छलावा है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा।
- (xxx) भारतीय उद्योग अभी भी कोविड के दुष्प्रभाव से उबर रहा है, जबकि चीनी उद्योग पहले ही ठीक हो चुका है और पूरी क्षमता पर चल रहा है, इसके अतिरिक्त चीन के पास परसल्फेट्स के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता है।
- (xxxi) चूंकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में मौजूदा व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं, और भारत में संबद्ध सामानों के लिए बढ़ती मांग से, यह आसन्न है कि चीन अपने निर्यात गहन तरीके से भारत को भेजेगा।
- (xxxii) चीन में परसल्फेट उत्पादकों की क्षमता उपयोग दर लगभग 45.5 प्रतिशत है और यह अतिरिक्त 221,052 मीट्रिक टन है।
- (xxxiii) निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा गैर-प्रतिभागिता यह दर्शाती है कि वे वर्तमान जांच के परिणामस्वरूप उन पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं।
- (xxxiv) संबद्ध देश पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा करने और घरेलू उद्योग को दुनिया भर में उपलब्ध सीमित उत्पादकों की सूची से हटाने के लिए पाटित कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात करके भारत में बढ़ती मांग का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।
- (xxxv) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत 2025 तक दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण उद्योग बनने की उम्मीद है। पॉलिमर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रमुख राजस्व उत्पादक साबित होने की संभावना है। विश्व भर में धातु और बढ़ते हुए उपभोक्ता उपकरणों की मांग में पॉलिमर के लिए बढ़ती हुई प्राथमिकता के कारण समीक्षा अवधि 2018-2023 के दौरान परसल्फेट बाजार के लिए प्रमुख राजस्व सृजक सिद्ध होने की संभावना है।
- (xxxvi) उपभोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में चिंतित नहीं है, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि केवल एक प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया है।
- (xxxvii) मेसर्स जे केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, मेसर्स रश्मि ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स सागर स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर उत्तरों में पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का उल्लेख नहीं है।
- (xxxviii) यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग में कीमतों में वृद्धि होगी और इसका प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कहने के समान है कि पक्षकारों को अनुचित कीमत वाले उत्पाद में निरंतर पहुंच होने देनी चाहिए और प्रयोक्ता उद्योग अनुचित कीमत वाली कच्ची सामग्री में पहुंच के बिना चल नहीं सकते।
- (xxxix) चूंकि केम इंटेल् ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर, प्राधिकार और भाग लेने का इरादा दायर नहीं किया, और उत्तर दायर न करने के लिए इस आयातक द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया था, अतः उनकी ओर से किए गए किसी भी अनुरोध को रद्द किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और संगत नियमावली और अनुबंध-III के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की है।

i. संचयी मूल्यांकन

36. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक है, और
- ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- क. संबद्ध सामान भारत में संबद्ध देशों से पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं की भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
38. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा।
39. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
40. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
41. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की कार्यवाही करते हैं। प्राधिकारी ने संगत पाटनरोधी नियमावली और अनुबंध-II के अनुसार घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है। क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, की जांच और समाधान निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

42. संबद्ध सामानों की मांग का निर्धारण सभी देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के साथ समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री को जोड़कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

मांग	मी. टन	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	110	145
अन्य भारतीय उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	104	58
संबद्ध देश – आयात	मी. टन	1,424	1,956	1,699	2,716
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	119	191
अन्य देश – आयात	मी. टन	230	469	47	90
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	204	20	39
कुल मांग/खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	108	144

43. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग 2017-18 में बढ़ी और उसमें 2018-19 में गिरावट आई तथा जांच की अवधि में पुनः बढ़ी।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं और हिस्सा

44. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयात मात्रा					
चीन	मी. टन	477	872	385	1,709
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	183	81	358
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. टन	947	1,084	1,314	1,007
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	139	106
संबद्ध देश	मी. टन	1,424	1,956	1,699	2,716
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	119	191
अन्य देश	मी. टन	230	469	47	90
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	204	20	39
कुल आयात	मी. टन	1,654	2,425	1,746	2,806
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	106	170

45. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में आधार वर्ष से 91% और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 61% तक वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि मई, 2019 तक संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू थे। इस प्रकार, जब पाटनरोधी शुल्क लागू थे, तब भी संबद्ध देशों से आयात काफी थे। मई, 2019 में शुल्क समाप्त होने के बाद काफी अधिक बढ़ गए।

ग. सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात

46. सापेक्ष दृष्टि में आयात नीचे दर्शाए गए हैं:

के संबंध में संबद्ध आयात	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	119	114	152
मांग	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	113	113	133

47. यह देखा जाता है कि उत्पादन के संबंध में आयात 2017-18 तक बढ़े और उनमें 2018-19 में थोड़ी गिरावट आई तथा जांच की अवधि में उनमें काफी वृद्धि हुई। जबकि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयातों में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है।

iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

48. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा तक कमी करना है या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में काफी मात्रा तक हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

49. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।

उत्पाद: परसल्फेट्स- चीन जन. गण.					
वर्ष	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयात मात्रा	मी. टन	477	872	385	1,709
आयात मूल्य	लाख रु.	291	528	234	875
मूल्यांकन योग्य मूल्य	रु./कि. ग्रा.	61	61	61	51
सीमा शुल्क	%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
सीमा शुल्क की राशि	रु./कि. ग्रा.	5	5	5	4
उप-कर/एसडब्ल्यूसी	%	3%	3%	10%	10%
उप-कर/एसडब्ल्यूसी की राशि	रु./कि. ग्रा.	0	0	0	0

पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	66	65	66	55.42
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	100	84
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	97	98
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	30-40	30-40	30-40	40-50

उत्पाद: परसल्फेट्स – संयुक्त राज्य अमेरिका

वर्ष	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयात मात्रा	मी. टन	947	1,084	1,314	1,007
आयात मूल्य	लाख रु.	765	877	1,145	804
मूल्यांकन योग्य मूल्य	रु./कि. ग्रा.	81	81	87	80
सीमा शुल्क	%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
सीमा शुल्क की राशि	रु./कि. ग्रा.	6	6	7	6
उप-कर/एसडब्ल्यूसी	%	3%	3%	10%	10%
उप-कर/एसडब्ल्यूसी की राशि	रु./कि. ग्रा.	0	0	1	1
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	87	87	94	86
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	108	99
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	97	98
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-30	10-20	0-10	20-30

50. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतें संचयी रूप से और अलग-अलग रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही हैं। इस प्रकार, घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात क्षति की अवधि के दौरान भी काफी थे क्योंकि वह विद्यमान पाटनरोधी शुल्क खपाने में सक्षम थे। यह तर्क दिया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।

ख. कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण

51. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। तथ्यपरक स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	105	113
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	97	98

52. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि 2017-18 में उत्पादन की लागत में गिरावट आई जब बिक्री मूल्य में भी गिरावट आई। इसके बाद जांच की अवधि में उत्पादन लागत में लगभग 33% तक वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री मूल्य समान स्तर पर बना रहा। इस प्रकार, घरेलू उद्योग बिक्री मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ अपनी कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था, परिणामस्वरूप आयात कीमतों का घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। यह तर्क दिया गया है कि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव किस्म-वार पाटित आयातों के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाता है क्योंकि पीपीएस के लिए जांच की अवधि में कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है जिनमें आयात घरेलू बाजार में नहीं आ रहे हैं। तथापि, एपीएस और एसपीएस के लिए कीमत ह्रास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

54. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	116	138
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	127	154
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	109	112
बिक्री मात्रा - घरेलू	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	110	145

55. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री 2017-18 तक बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि को देखते हुए उत्पादन और मांग में वृद्धि की मात्रा तक नहीं बढ़ी है।

ख. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

56. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
लाभ	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	77	61
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	88	106
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	89	116
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	44	50

57. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2017-18 में बढ़ी और उसके बाद उसमें 2018-19 एवं जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।
- 2017-18 तक नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि के साथ 2018-19 में उसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष और 2016-17 में अच्छी आय कमा रहा था परंतु क्षति अवधि के दौरान इसमें काफी गिरावट आई।
- घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि एपीएस और एसपीएस दोनों के लाभ में भी जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है, और पीपीएस के लाभ में 2017-18 में गिरावट आई है और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है क्योंकि जांच की अवधि में पीपीएस के कोई आयात नहीं हैं। यह आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के बीच सीधा संबंध दर्शाता है। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है और अपनी कीमतों को आयात कीमतों के समान बनाए रखने के लिए मजबूर हुआ है, जिससे वर्तमान जांच की अवधि में गिरावट आई।

ग. मांग में बाजार हिस्सा

58. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

मांग में बाजार हिस्सा	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	102	100
अन्य भारतीय उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	100	44
संबद्ध देश – आयात	%	***	***	***	***
अन्य देश – आयात	%	***	***	***	***
कुल	%	100	100	100	100

59. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कुछ गिरावट के साथ क्षति अवधि के दौरान समान स्तरों पर रहा है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में भी जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- जांच की अवधि में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। अन्य देशों की बाजार हिस्से में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों ने न केवल भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से को बल्कि अन्य देशों के बाजार हिस्से को भी लिया।
- घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बिक्री कीमतों और पाटनरोधी शुल्क से समझौता करने के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों की काफी मात्रा की मौजूदगी के कारण अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है, जिसने घरेलू उद्योग के संभावित बाजार हिस्से और अन्य उत्पादकों तथा अन्य देशों के वास्तविक बाजार हिस्से को लिया है।

घ. रोजगार और मजदूरी

60. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	116	129
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	641	779	902

61. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड. मालसूची

62. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

स्टॉक (मात्रा)	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औसत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	455	509

63. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में 2018-19 और जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग, क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद संबद्ध सामानों की बिक्री करने सक्षम नहीं रहा है।

च. पूंजी जुटाने की क्षमता

64. घरेलू उद्योग ने हाल ही में एक निवेश किया है। इस प्रकार, पूंजी जुटाने की क्षमता अब तक प्रभावित नहीं हुई है। यदि घरेलू उद्योग को ऐसी विस्तारित क्षमता का उपयोग करने से रोका जाएगा, तो पूंजी जुटाने की उसकी क्षमता लड़खड़ा सकती है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

65. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे कीमत कटौती हो रही है। कीमत कटौती से भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ है। संबद्ध सामानों की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है और इसीलिए वह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकती।

झ. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

66. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की गई है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से प्रत्येक पीसीएन की पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटीयों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन का परिकलन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करके किया गया है और उस उत्पादन पर प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुबंध-III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। इस प्रकार निर्धारित प्रत्येक पीसीएन के लिए क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमतों के साथ तुलनीय पीसीएन के लिए की गई है ताकि क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जा सके:

क्षति मार्जिन संयुक्त राज्य अमेरिका	एपीएस	एसपीएस	औसत
आयात मात्रा (मी. टन)	429	578	1,007
	अमे. डॉ./मी. टन		अमे. डॉ./मी. टन
क्षति रहित कीमत	***	***	***
पहुँच मूल्य	1,001	1,369	1,212
क्षति मार्जिन	(***)	***	***
क्षति मार्जिन %	(***)	***	***
क्षति मार्जिन % (रेंज)	(20-30)	20-30	0-10
क्षति मार्जिन चीन	एपीएस	एसपीएस	औसत

आयात मात्रा (मी. टन)	1,649	60	1,709
	अमे. डॉ./मी. टन		अमे. डॉ./मी. टन
क्षति रहित कीमत	***	***	***
पहुँच मूल्य	754	1,315	774
क्षति मार्जिन	***	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***	***
क्षति मार्जिन % (रेंज)	0-10	20-30	0-10

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

68. अन्य देशों से आयात या तो मात्रा में कम हैं या संबद्ध देशों से आयात कीमतों की तुलना में अधिक कीमत पर हैं।

ख. निर्यात निष्पादन

69. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

70. क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हो सकती।

घ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

71. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार किया है। घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति केवल संबद्ध सामानों के संबंध में है।

ङ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

72. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती हो।

च. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

73. यह नोट किया जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को यह क्षति मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन के कारण नहीं थी।

ट. प्रकटन के बाद टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

74. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन के बाद की टिप्पणियां नीचे दिए अनुसार हैं:-

- क) पीओआई के दौरान संबद्ध किसी भी देश से भारत में पीपीएस का आयात नहीं किया गया है। एसपीएस और एपीएस के लिए अलग-अलग पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं, आयातों के न होने की स्थिति में पीपीएस के लिए ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है। उत्पाद के विषय में पीपीएस को शामिल करने का अभिप्राय यह होता है कि एपीएस और एसपीएस के लिए निर्धारित किया गया शुल्क पीपीएस पर भी लागू होगा, जो एक न्यायसंगत पहल नहीं हो सकती। विचाराधीन उत्पाद के विषय में पीपीएस को शामिल करने के लिए प्राधिकारी अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार कर सकते हैं।
- ख) यूएसए के लिए यथेष्ट पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य की अप्रमाणित पद्धति का परिणाम है और इसे वास्तविक नहीं माना जा सकता है।
- ग) वर्तमान क्षति मार्जिन में गहन जांच की अपेक्षा होती है क्योंकि यह चीन और यूएसए के लिए समान रेंज में होती है। यह सही नहीं हो सकती है क्योंकि यूएसए से एसपीएस और एपीएस कीमतें चीन की कीमतों से 36 प्रतिशत अधिक होती हैं।
- घ) यूएसए और चीन से अलग-अलग आयात प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इन देशों से आयात अनुत्तुलनीय हैं और इनकी अलग-अलग जांच होनी चाहिए।
- ङ.) आवेदकों के लिए लाभप्रदता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी अथवा गिरावट का समर्थन करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं। घरेलू उद्योग की समग्र मात्रा और कीमत संबंधी मापदण्ड सन्तुलित स्थिति को दर्शाते हैं। पीओआई के दौरान लाभों में हुई मामूली सी गिरावट पूर्ववर्ती वर्ष में बहुत अधिक लाभों की वजह से थी।
- च) एपीएस और एसपीएस के बीच में कीमतों में अन्तर होने की वजह से उत्पाद किस्म आधार पर पाटनरोधी शुल्क की भी सिफारिश की जानी चाहिए क्योंकि भारित औसत मार्जिनो/शुल्क देयता का निर्धारण करने के लिए कोई आधार नहीं होता है। जूट उत्पाद जैसे विभिन्न मामलों में किस्म-वार/पीसीएन वार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है।
- छ) यूएसए से हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध नहीं है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

75. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन के बाद की टिप्पणियां नीचे दिए अनुसार हैं:-

- क) आवेदक कंपनी पर कथित संबद्ध कम्पनियों का कोई संबंध अथवा नियंत्रण नहीं है। कथित संबद्ध कम्पनियों ने यह प्रमाणित किया है कि इन कम्पनियों के द्वारा पीओआई के दौरान कोई निर्यात नहीं किए गए थे।
- यूनाइटेड इनिशिएटर्स हीफी कं. लि., चीन, यूआई जीएमबीएच की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। वे चीन से संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण एवं निर्यात करने के कार्य में शामिल है।
 - यूनाइटेड इनीशिएटर्स हीफी कं. लि., चीन ने जांच अवधि के दौरान भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।
 - यूआई जीएमबीएच की कोई भी अन्य संबद्ध कंपनी चीन से संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण एवं निर्यात करने में शामिल नहीं है।
- ख) यूएसए में संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने में यूनाइटेड इनिशिएटर इंक, यूएसए लगी हुई नहीं है। यह यूएसए के घरेलू बाजार में परसल्फेट्स के व्यापार में लगी हुई है। यूनाइटेड इजीशिएटर इंक, यूएसए ने जांच अवधि के दौरान भारत के लिए परसल्फेट्स का निर्यात नहीं किया है। प्रस्तावित पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से बड़े हुए आयात संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास अधिक उत्पादन क्षमता, निर्यातकों के लिए आकर्षित हो रहे भारतीय बाजार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के बारे में तीसरे देश के उपाय तथा शेष विश्व की तुलना में चीन के कोविड-19 से तेजी से उभरने को ध्यान में रखते हुए वस्तुतः क्षति होने का खतरा है।
- ग) कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का केवल उन्हीं लेन-देनों पर ही विचार करते हुए निर्धारण करना चाहिए जिनके आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य एवं क्षतिरहित कीमत से कम है।

- घ) विचाराधीन उत्पाद के हरेक लेन-देन की जांच के आधार पर कीमत में कटौती करने का एक अकेला मार्जिन सुनिश्चित करने हेतु पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार कोई अपेक्षा नहीं होती है। घरेलू उद्योग ने कोठारी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट के निर्णय के बारे में घरेलू उद्योग ने संदर्भ दिया है, जिसमें क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए एनआईपी से कम लेन-देनों पर विचार करने की अनुमति दी थी।
- ड.) पीओआई के दौरान आयात कीमत में काफी गिरावट हुई है और पीओआई के बाद भी गिरावट आयी है। अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शुल्क वर्तमान प्रचलित कीमतों के आधार होने चाहिए। पाटन आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पीओआई के औसत पहुंच मूल्य के आधार पर शुल्क स्तर काफी पर्याप्त नहीं होंगे।
- च) जांच में केवल एक ही प्रयोक्ता ने भाग लिया और पाटन के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं करा सकें। प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का, यदि लगाया गया, समग्र प्रभाव, न्यूनतम होगा। संबद्ध वस्तुओं के मुख्यतः उपयोग वस्त्र और रसायन उद्योगों में होता है। प्रतिपादन पर निर्भर करते हुए, एपीएस के लिए खपत का पैटर्न कुल लागत का 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत है क्योंकि उद्योग को ध्यान में न रखते हुए केवल इसका उपयोग एक आक्सीकरण एजेंट के रूप में होता है। इसी तरह, एसपीएस के लिए खपत पैटर्न लगभग 1.3 प्रतिशत से 1.65 प्रतिशत तक है। अतएव, 100 कि.ग्रा. के अन्तिम उत्पाद के एक बैच के द्वारा मौटे तौर पर केवल 0.5 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत तक की खपत होगी। अन्ततः प्रभाव न्यूनतम होगा।
- छ) यूएसए में सामान्य मूल्य को उस कीमत के रूप में विचार करना चाहिए जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं को अमरीकी बाजार में बेचा जा रहा है। सामान्य मूल्य के लिए कीमत को खपत कीमत के रूप में लिया जाएगा, न कि उस कीमत के रूप में, जिस कीमत पर आवेदक कंपनी द्वारा उसकी संबद्ध कंपनी के लिए इसे बेचा गया था। जैसा कि प्राधिकारी ने नोट किया है, पुनः बिक्री की कीमत की अमरीका में आयात कीमत के साथ तुलना की जा सकती है, जो संबद्ध वस्तुओं की खपत कीमत भी है तथा प्राधिकारी ने अधिकारपूर्ण इस पर विचार किया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

76. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों की पुनरावृत्ति हुई है जिनके बारे में निष्कर्ष निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफों में उपयुक्त जांच पहले ही कर ली गई है तथा पर्याप्त समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा प्रकटन के बाद टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की है:
- क. पीपीएस का आयात नहीं किया जा रहा है, अपितु इसे उत्पाद के विषय में शामिल किया है, इस दावे के बारे में यह दोहराया जाता है कि एसपीएस, एपीएस और पीपीएस सभी एक विचाराधीन उत्पाद के रूप में हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीओआई के अन्तर्गत प्रत्येक किस्म के विचाराधीन उत्पाद का आयात करना कानून के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा और कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, तब तक इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाना अपेक्षित होता है। पूर्ववर्ती जांचों में भी इस किस्म के आयात थे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि तीन किस्मों के परसल्फेट्स इसी सामान्य प्रयोजन का कार्य करते हैं। उपभोक्ता सामान्य तौर पर एक अल्प अवधि के दौरान एक किस्म से दूसरी किस्म की ओर नहीं जाते हैं। तथापि, कई अनुप्रयोग हैं जहां पर सभी तीनों किस्मों के परसल्फेट्स का परस्पर बदल-बदल कर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पादक परस्पर बदल-बदल कर सभी तीनों किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर एपीएस, पीपीएस और एसपीएस एक विचाराधीन उत्पाद की किस्में हैं तथा आयात के प्रयोजनों के लिए इन्हें पृथक-पृथक देखा जा सकता है। उत्पादन प्रक्रिया की प्रतिमोच्यता (फंजीविलिटी) तथा एपीएस, एसपीएस और पीपीएस के अधीन उत्पाद एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षति अवधि के दौरान पीपीएस के आयात हुए हैं, तो प्राधिकारी पीपीएस को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर करना अनुचित मानते हैं।
- ख. यूएसए के लिए पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य अप्रामाणिक पद्धति का परिणाम है, इस तर्क के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि पद्धति के बारे में पर्याप्त रूप से बता दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि यूएसए के किसी भी

उत्पादक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी के समक्ष (क) आवेदक उद्योग द्वारा यूएसए के लिए किए गए निर्यातों तथा (ख) आवेदक कम्पनियों में से एक कम्पनी की पुनः बिक्री कीमत के रूप में रखे प्रमाणों के बारे में प्राधिकारी ने जांच की है। यूएसए में व्यापारी की पुनः बिक्री कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध करायी गई थी तथा (ग) यूएसए में प्रचलित कीमत के रूप में यूएसए में आयात संबंधी प्रस्तुत किए गए प्रमाण की सूचना की प्राधिकारी ने जांच की है और इस बारे में यूएसए के पास प्रत्येक किस्म के उत्पाद की सूचना है। प्रमाण की जांच करने के उपरान्त प्राधिकारी ने यूएसए के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री कीमत पर विचार करने के लिए इसे उपयुक्त पाया जिसकी यूएसए में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के साथ तुलना की जा सकती है।

- ग. क्षति मार्जिन का निर्धारण करने की पद्धति गलत प्रतीत होती है और भारित औसत मार्जिनों के बारे में विचार किया जाना चाहिए, इस तर्क के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारित औसत क्षति मार्जिनों पर विचार किया गया है।
- घ. वर्तमान मामले में संचयी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और यूएसए से हुए आयातों से क्षति नहीं हो रही है, इस तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि संचयी मूल्यांकन की सभी अपेक्षाएं मौजूद हैं तथा ऐसी शर्तों के पूर्ण होने पर प्राधिकारी ने क्षति को संचित करने के लिए इसे उपयुक्त पाया है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान यूएसए से आयातों में गिरावट आयी है, इस तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान यूएसए से आयात काफी अधिक हुए हैं। यद्यपि, पूर्ववर्ती वर्ष से पीओआई के दौरान इनकी मात्रा कुछ कमी को दर्शाती है, परन्तु जब घरेलू उद्योग की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तब पीओआई के दौरान यूएसए से आयात कीमतों में काफी गिरावट आयी है। यूएसए से आयात निर्बाध और सापेक्ष शर्तों पर काफी हुए हैं। यूएसए से आ रही संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमतों में कटौती सकारात्मक हैं। अतएव, चीन के आयातों के साथ-साथ यूएसए से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ङ. एपीएस और एसपीएस आयातों का हिस्सा चीन जन. गण. और यूएसए के मामले में भौतिक रूप से भिन्न है। जबकि चीन जन. गण. से एसपीएस का आयात चीन जन. गण. से पीयूसी के कुल आयात का केवल ***% है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में एसपीएस का हिस्सा ***% (उपरोक्त पैरा 65) है। इसके अलावा, एसपीएस और एपीएस के पहुंच मूल्य के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर है, जैसा कि ऊपर पैरा 65 की तालिका से स्पष्ट है। कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी ने पहले एपीएस और एसपीएस के लिए अलग-अलग क्षति मार्जिन निर्धारित किया है; और उसके बाद संबद्ध आयात मात्रा के आधार पर भारित औसत का निर्धारण किया है। यह देखा गया है कि चीन के मामले में क्षति मार्जिन एसपीएस और एपीएस दोनों के लिए यूएसए के मामले में क्षति मार्जिन से अधिक है। यह भी देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से एसपीएस का आयात मूल्य चीन जन. गण. से केवल 4% अधिक है। हितबद्ध पक्षकारों ने औसत कीमतों की गलत तुलना की है।

ठ. घरेलू उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

77. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पूरी तरह समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके जो कि सामान्य रूप से देश हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं की उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
78. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या एडीडी लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसी के लिए, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या जांच के तहत उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा।

यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षों के रिकॉर्ड और हितों की जानकारी पर विचारणीय है।

79. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उसके संचालन पर एडीडी के संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गए उत्पाद की अदला-बदली, घरेलू उद्योग की, स्रोत बदलने की क्षमता उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव ऐसे कारकों के बारे में जानकारी मांगी, जिनसे एडीडी के कारण पैदा स्थिति से समायोजन में तेजी आने या देरी होने की संभावना है।
80. दो आयातक और एक उपयोगकर्ता, अर्थात् मैसर्स जे केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (उपयोगकर्ता), मैसर्स रश्मि ट्रेडिंग कंपनी और मैसर्स सागर स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर दिये। हालांकि उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी या प्रस्तुतिकरण प्रदान नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि कर्तव्यों से उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी जिससे उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं के लिए एडीडी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रारूप निर्धारित किए हैं, और यह विस्तार से बताया है कि एडीडी लगाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि इच्छुक पार्टियों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ उपयोगकर्ता उद्योग पर एडीडी के प्रभाव को स्थापित नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उपभोक्तृ पर अनुशासित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है और प्रस्तुत किया है कि प्रभाव बहुत कम हैं।
81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद मुक्त श्रेणी के अंतर्गत हैं और इसलिए, विभिन्न देशों से मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धताको प्रभावित नहीं करेगा। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न वैश्विक कंपनियों हैं। अतीत में जापान, तुर्की और ताइवान भारत में उत्पन्न होने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच की गई है जो यह दर्शाती है कि ये वे देश हैं जहां कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है और जहां से भारत को निर्यात किया जा था। ईयू और यूएसए भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। इस प्रकार संबद्ध वस्तुओं के आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं। इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित करेगी और न ही एकाधिकार पैदा होगा।
82. ईयू और यूएसए ने भी चीन जन.गण. से क्रमशः यूएसए और ईयू में विचाराधीन उत्पाद के आयात की जांच की है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उक्त आयातों पर यह पता लगाने पर शुल्क लगाया है कि आयातों से उनके घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। चीन के खिलाफ शुल्क क्रमशः 24 साल और 14 साल से लागू हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्कों की मात्रा क्रमशः यूएसए द्वारा 119 प्रतिशत और यूरोपीय संघ द्वारा 24.5 -71.8 प्रतिशत है जो कि पाटन के उस स्तर को इंगित करता है जिसका उपयोग चीन अन्य देशों में कर रहा है।
83. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे संबद्ध वस्तुओं की कीमतों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए परिमाणित सूचना प्रस्तुत की है कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत कम है और इसका अंतिम प्रयोक्ता पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबद्ध वस्तुओं का मुख्य रूप से कपड़ा और रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। सूत्रीकरण के आधार पर, एपीएस के लिए खपत पैटर्न कुल लागत का 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत है क्योंकि इसका एक मात्र उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में होता है चाहे उद्योग कुछ भी हो। इसी तरह, एसपीएस के लिए खपत पैटर्न लगभग 1.3 प्रतिशत से 1.65 प्रतिशत है। इस प्रकार, 1000 किग्रा. अंतिम उत्पाद का एक बैच मोटे तौर पर केवल 0.5 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत की खपत करेगा। इसका अंतिम प्रभाव नगण्य होगा।

84. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रस्तावित एडीडी से संभावित प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं किया है, भले ही यह माना जाता है कि एडीडी लगाने से विनिर्मित उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए, अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अत्यधिक महत्वहीन होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना एवं घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने के लिए और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद करना है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

85. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान ही है। पीपीएस विचाराधीन उत्पाद का एक रूप है और इसे उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
 - ग. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रकार के हिसाब से पाटन अंतर का निर्धारण किया गया है और अन्तर काफी अधिक है।
 - घ. घरेलू उद्योग को काफी क्षति हुई है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टियों में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की मात्रा में संपूर्ण शतों पर जांच की अवधि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमत कटौती का अन्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लगभग 15-25 प्रतिशत और चीन के लिए लगभग 40-50 प्रतिशत है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। क्षमता वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा समान दायरे में रहा है। लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। पीओआई में लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। 2017-18 तक नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में वृद्धि हुई है और पीओआई में मामूली वृद्धि के साथ 2018-19 में गिरावट आई है।
 - ड. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - च. एडीडी के प्रभाव को मापने के लिए उपयोगकर्ताओं को सभी प्रारूप प्रदान करने के बावजूद और यह विस्तृत करने के बावजूद कि एडीडी लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा, किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रासंगिक मात्रात्मक जानकारी प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ उपयोगकर्ता उद्योग पर शुल्क नहीं लगाने से संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है, प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क जनहित में होगा।
86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन संबंधी पहलू पर सूचना उपलब्ध कराने के पर्याप्त अवसर भी दिए गए थे। नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है, इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

87. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क संबंधी नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के अंतर और क्षति के अपेक्षाकृत कम अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। इसलिए, प्राधिकारी मूल शुल्क तालिका के कॉलम (3) में वर्णित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर कॉलम (7) में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। ये शुल्क इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1.	2833 40 और 283340 00	अमोनियम परसल्फेट (एपीएस)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	19	एमटी	यूएस डालर
2.	2833 40 और 283340 00	सोडियम परसल्फेट (एसपीएस)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	201	एमटी	यूएस डालर
3.	2833 40 और 283340 00	पोटेशियम परसल्फेट (पीपीएस)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	32	एमटी	यूएस डालर
4.	2833 40 और 283340 00	अमोनियम परसल्फेट (एपीएस)	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	19	एमटी	यूएस डालर
5.	2833 40 और 283340 00	सोडियम परसल्फेट (एसपीएस)	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	201	एमटी	यूएस डालर
6.	2833 40 और 283340 00	पोटेशियम परसल्फेट (पीपीएस)	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	32	एमटी	यूएस डालर
7.	2833 40 और 283340 00	अमोनियम परसल्फेट (एपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	शून्य	एमटी	यूएस डालर

8.	2833 40 और 283340 00	सोडियम परसल्फेट (एसपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	344	एमटी	यूएस डालर
9.	2833 40 और 283340 00	पोटेशियम परसल्फेट (पीपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	100	एमटी	यूएस डालर
10.	2833 40 और 283340 00	अमोनियम परसल्फेट (एपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी उत्पादक	शून्य	एमटी	यूएस डालर
11.	2833 40 और 283340 00	सोडियम परसल्फेट (एसपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी उत्पादक	344	एमटी	यूएस डालर
12.	2833 40 और 283340 00	पोटेशियम परसल्फेट (पीपीएस)	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी उत्पादक	100	एमटी	यूएस डालर

ढ. आगे की प्रक्रिया

88. केन्द्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपील जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, उपयुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th September, 2021

Case No. (AD-OI-21/2020)

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Peroxosulphates (Persulphates) originating in or exported from China PR and USA.

F. No. 6/25/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. The Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) received an application (also referred to as “the petition”) from M/s UI VR Pvt. Ltd. and M/s Calibre Chemicals Pvt Ltd. (hereinafter referred to as “the applicants” or “the petitioners” or “the domestic industry”) requesting initiation of an anti-dumping investigation under the Act and the Rules on the imports of Peroxosulphates (Persulphates) (hereinafter also referred to as “the product under consideration” or “the PUC” or “the subject goods”) originating in or exported from China PR and USA (hereinafter also referred to as “the subject countries”).
3. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 06/25/2020-DGTR dated 28th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed in the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of the Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice No. 06/25/2020-DGTR dated 28th September, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 28th September, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent

along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

- f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Fulida Industry Co. Ltd., China
 - ii. Hebei Jiheng Group Co. Ltd, China
 - iii. Shanxi Baohua Technologies Co. Ltd. China
 - iv. Dry Chlorine Corp (DCC), China
 - v. Degussa Initiators GmbH & Co. KG, USA
 - vi. Industrial Chemicals Group, USA
 - vii. E.I. Dupont Nemours, USA
 - viii. FMC Corporation, USA
- g. In response to the above notification, none of the exporters/producers responded.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Gujarat Themis Biosyn Ltd
 - ii. Nicholas Piramal India Ltd
 - iii. Padma Agencies
 - iv. Aurobindo Pharma Ltd
 - v. Artek Surfin Chemicals Ltd
 - vi. Novartis India Ltd
 - vii. Zydex Industris
 - viii. Venus Insulators Pvt. Ltd.
- i. In response, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions:
 - i. M/s Jay Chemical Industries Pvt. Ltd.
 - ii. M/s Rashmi Trading Company
 - iii. M/s Sagar Speciality Chemicals Pvt. Ltd.
 - iv. M/s Chem Intel
- j. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to restrictions on physical movements owing to ongoing global Covid-19 pandemic.
- k. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury examination period is the period from 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017 -31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019 and the period of investigation.
- l. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the subject goods for the injury period, including the period of investigation, and analysed the data after due examination of the transactions.
- m. Verification of the data provided by the domestic industry and the responding exporters was concluded to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

- n. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits for the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 01st June, 2021. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- p. The submissions made by the interested parties, the arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding.
- q. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of this final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant.
- r. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- s. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 01.09.2021 and the interested parties were allowed time up to 07.09.2021 to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- t. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- u. '****' in the final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.24.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the other interested parties

5. The following are the submission made by the other interested parties with regard to the product under consideration and the like article:
 - i. When there are no imports of PPS, the requirement of the PUC that the product should originate in or be exported from the subject countries is not met. The product type not imported into India during the POI warrants exclusion from the PUC.
 - ii. The type-wise identification of the product or a PCN methodology is devised only when a significant difference in the cost and the price is demonstrated between inter-se types and there is no precedence that a product type identified which was not imported was still included in the PUC.

C.2 Submissions made by the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and the like article:
 - i. The product under consideration is ‘Peroxosulphates’, commonly known as ‘Persulphates’. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal Salts which include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS).
 - ii. The Chemical formula of the above-mentioned three types of Persulphates is $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ respectively. The three types of Persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries. All the three salts are one and the same product which has a ‘White Crystalline Powder’ appearance, soluble in water, decomposes slowly and liberates oxygen while absorbing moisture.
 - iii. The three types of persulphates serve the same general purpose. The consumers normally do not switch one type with the other type in a short run. There are several applications where all three types of Persulphates can be used interchangeably.
 - iv. The producers in the subject countries can interchangeably produce all the three types of Persulphates and can switch from dumping of one type persulphates to dumping of the other type with ease.
 - v. Persulphates is classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheadings 2833 40 and 283340 00. However, the said customs classifications are only indicative, and the same are not binding on the scope of the investigation.
 - vi. APS, PPS and SPS are part of the subject goods and cannot be seen in isolation for the import purposes. The Authority in previous investigations too has treated all these grades as one product.
 - vii. The contention of the importers/users that there is no import of PPS is without any factual basis. No imports of PPS during the POI should not be misunderstood with no imports of PPS at all and thus cannot be a ground to exclude the product type.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration in this investigation is “Peroxosulphates”, commonly known as “Persulphates”. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal Salts which include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS), and Sodium Persulphates (SPS). The Chemical Formulae of these Persulphates are $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ respectively. The three types of persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries and one can be substituted for another. All the three salts are nothing but different forms of the same product.
8. The domestic industry has requested to include all the three forms of the subject goods in the scope of the product under investigation and has also relied on the investigations undertaken by USA and EU against imports of persulphates from China, wherein all the three forms of Persulphates have been considered as one “product under consideration”. It is noted that the Authority has in all the previous investigations considered all types of persulphates as one product under consideration. Further, separate dumping margin and injury margin has been determined having regard to the difference in cost and price of the subject goods. It has also been contended by the other interested parties that PPS has not been imported in the POI and thus should not be included in the PUC. In this regard, it is noted that since there is documentary evidence that there are imports of PPS during the injury period and further that the domestic industry is producing PPS, the Authority finds it appropriate to include PPS in the scope of the product under consideration.
9. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the product under consideration exported from the subject countries and the subject goods produced by the Indian industry. The interested parties have also not claimed any difference in the goods produced by the domestic industry and the imported product. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the subject goods exported from the subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

10. The Authority holds that the goods produced by the applicant domestic industry are “like article” to the goods exported from the subject countries in terms of the AD Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

11. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope and the standing of the domestic industry:
- i. The details available show that the applicant VR Persulphates Pvt Ltd is now UI VR Private Ltd. The inconsistency needs clarification.
 - ii. UI VR Private Ltd is now a joint venture with United Initiators GmbH (UI). Relation of the Company with UI necessitates examination of relation of UI VR with producers/exporters of the subject goods in China PR and USA since UI has related producers/exporters in China PR and USA.
 - iii. The Petitioner did not disclose the fact that UI VR Private Ltd became a joint venture in 2018 with a German major, United Initiators GmbH (UI), and was making misleading claims that the entities are MSME etc.
 - iv. The Authority is urged to seek information from the Customs authorities to examine whether any of the imports of subject goods was from a related party. Further, UI VR Pvt. Ltd. should be directed to provide clarity on its relationship with such parties including details of any export of subject goods from any of such related entities of UI VR.
 - v. The failure of the company to disclose its relationship with UI shows that the declaration is not trustworthy, and a thorough examination of such relations is essential. To that extent, the standing of the petitioner entity concerned here as constituent of DI is disputed.

D.2 Submissions made by the domestic industry

12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope and the standing of the domestic industry:
- i. The application has been filed by M/s UI VR Pvt. Ltd. and M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd. The applicants have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any importer in India or producer/exporter from the subject countries.
 - ii. The applicants constitute “a major proportion” of the total Indian production and are thus eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the requirement of standing under the Rules.
 - iii. VR Persulphates Pvt. Ltd. formed a joint venture with a German Company named United Initiators (UI), having 50% stake and consequently, the name of the company got changed from VR Persulphates Pvt Ltd to UI-VR Private Limited. The changed name was mentioned in the letterhead of the company and the information was available in the public domain as well.
 - iv. The effect of Joint Venture did not change the legal position of the applicant company for the purposes of this investigation, as the company is still no way related to the exporter or nor an importer of the subject goods in India. The company remains the same as in the earlier investigation and is still one of the leading manufacturers of persulphates in India.
 - v. The statement by the user/importer that the letterhead of the applicant company cannot be believed completely lacks logic. The letterhead contains the changed name of the applicant company which importers/users also alleged and acknowledged. Just because the initiation notification mentions the earlier name of the company does not mean that the applicant suppressed any facts.
 - vi. There was an error due to oversight when the applicant copied part of the contents from the previous petition. However, this in no way vitiates the present proceedings.
 - vii. The applicant has not suppressed or concealed any facts from the Authority. This is evident from the letterhead having the applicant’s name as UI-VR Private Limited, which was used by the applicant on various occasions before the investigation to reply to the queries raised by the officers through emails. The Authority has already verified various information filed by the applicant.

- viii. The applicants never concealed any fact from the Authority and the Authority may issue any notification/corrigendum it deems fit. However, the domestic industry considers that no corrigendum is necessary.
- ix. The joint venture does not have any impact on the relationship criteria of UI VR. Thus, it does not impact the eligibility of the applicant company. Post the joint venture, the applicant company is not related to the German company. None of the parties mentioned by the importer/user are related to UI VR and the applicant company is not related to any exporter. Thus, UI VR qualifies all the criteria of the Rules and is an eligible domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

- 13. The application has been filed by M/s UI VR Pvt. Ltd. and M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd. There are two other producers of the subject goods in India apart from the applicants, namely, M/s Gujarat Persalts Pvt. Ltd and Yoyo Chemicals. The applicants account for 96% of the domestic production of the like article in India. The applicants have not imported the subject goods from the subject countries and are not related to any exporter or importer in India.
- 14. Other interested parties have contended that the domestic industry has concealed the fact of merger of VR Persulphate and a German major, namely, United Initiators GmbH (UI) and now the name of the company has changed to UI VR Pvt Ltd. The domestic industry has replied stating that this fact was available in public domain and there was an inadvertent error on their part that they did not change the name of the applicant in the application and carried on with the old name. However, the authorisation letter filed on behalf of UI VR Pvt Ltd contained the new name of the company and the same was shared with all the interested parties.
- 15. It is noted that V R Persulphate entered into a 50% joint venture with a German company United Initiators GmbH (UI). Post-merger, United Initiator holds 50% shares of V R Persulphate. The companies related to UI in China or USA have not exported the subject goods to India during the POI. Thus, the joint venture does not vitiate the eligibility of the applicant company to be treated as the domestic industry under Rule 2 (b).
- 16. As per the evidence available on record, the production of the applicant companies accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. ISSUES OF CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by other interested parties

- 17. No submissions were made by the other interested parties with regard to confidentiality.

E.2 Submissions made by the domestic industry

- 18. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
 - i. The questionnaire responses filed by the importers/users are grossly deficient and violate the norms of confidentiality.
 - ii. None of the importers have filed the non-confidential version of the response in the prescribed manner and all the responses are in complete disregard to the trade notice 10/2018 dated 07.09.2020, thereby handicapping the domestic industry to provide any meaningful comments to the information filed by them.

E.3 Examination by the Authority

- 19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

20. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by the various interested parties through circulation of email.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

21. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

"the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

F.1 Submissions made by other interested parties

22. Various submissions made by the interested parties with regard to the normal value, the export price and the dumping margin and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
- i. The claims of the petitioners with respect to the dumping margin in case of USA should be subject to strict scrutiny as the whole claim is made without disclosing the fact that UI VR has made substantial exports of subject goods to its related party in USA and the normal value considered clearly covers related party transactions which is not disclosed to the Authority till date.

F.2 Submissions made by the domestic industry

23. Various general submissions made by the domestic industry are as follows:
- i. Sufficient evidence and details are provided by the applicants regarding the consumption price in USA. Since imports into the country are intended for consumption within the subject country, the price thereof can invariably serve as best available information with regard to the price of goods destined for consumption in the country.

- ii. Normal value based on the consumption price of the subject goods in the subject country should always be on the higher footing than the constructed normal value.
- iii. Reliance was placed on past investigations, wherein the Authority considered normal value on the basis of import price into the subject countries at the stage of preliminary findings as well as final findings and also in the anti-dumping investigation concerning imports of “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) – Whether or not processed into compound originating in or exported from China PR and Korea RP [F.No.6/3/2019-DGTR].
- iv. The result of ordinary course of trade (OCT) test is not to reduce the normal value but to enhance the normal value. Hence, in any case, the importer (or exporter) cannot have a grievance on this account and cannot plead inappropriateness of the methodology. The domestic industry itself has contended adoption of normal value on this basis and, therefore, the fact that the Authority may not be able to apply OCT test is entirely irrelevant for the purpose.
- v. The Authority is required to determine ex-factory price of the producer in US and not ex-factory price of the producer in India. The methodology applied for determining injury margin is relevant in this regard. If Authority considers landed price of imports at port as synonym to ex-factory Non-Injurious Price, by corollary, it should be considered that price at US port is synonym with ex-factory price of the US producer.
- vi. The contention that the price proposed by the domestic industry is to a related party and is unreliable has no basis. The US party has sold the product at a price 10% higher than the price at which it has procured the material. Thus, if the actual selling price of the US producer is to be considered, it would be seen that it will further enhance the normal value.
- vii. The applicants have submitted the calculation of landed price of the affiliate company in USA. The normal value in the USA will be considered as the price at which the subject goods are being sold in the US market. The price for the normal value will be taken as consumption price, not the price at which it was sold by the applicant company to its affiliate company. The affiliate company will not sell the subject goods in the USA market as it is, but will also add its margin.
- viii. The domestic industry has not made any admission that they are undercutting the price in the USA market. The submission of the domestic industry is that the exports from India are at a price lower than the price at which the US producer is selling the product in their domestic prices. Hence, the normal value should be considered as the import price (after all adjustments) and the margin by which the US producer is selling the product at a higher price in its domestic market.
- ix. The selling price at which UI VR Pvt. Ltd. sells to the affiliate party is at arms-length, and the transactions between the exporter and importer are unaffected by the relationship.
- x. According to the facts, the actual invoice price reported by the petitioner is of higher degree of evidence than the Constructed Normal Value for two reasons – (a) the rule provides a clear hierarchy between selling price and cost of production, (b) while the selling price is surrogate for the US producer’s price, the cost of production is surrogate for the US producer’s cost. Thus, in any way, this information cannot be disregarded.
- xi. The Authority has routinely adopted trade journal prices for the purpose of determination of normal value. In the present case the petitioner has provided information with regard to actual purchase price and that information pertains to significant volume of exports which is quite significant considering the imports into India.
- xii. The applicants have submitted the calculation of landed price of the affiliate company in USA. Normal value in USA will be considered as the price at which the subject goods are being sold in the US market. The price for normal value will be taken as consumption price, not the price at which it was sold by the applicant company to its affiliate company. The affiliate company will not sell the subject goods in USA market as it is, they will also add their margin.

- xiii. None of the exporters has participated in the investigation and thus not disputed that the subject goods are being dumped and the same was also not disputed by the limited participation of importers.

F.3 Examination by the Authority

Market Economy Status for Chinese producers

24. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

25. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
26. It is noted that none of the producers/exporters from China has participated in the investigation and filed the exporter questionnaire. Therefore, the normal value computation is required to be done as per the provision of para 7 of Annexure I of the Rules.

I. China PR**a. Determination of the Normal Value for China PR**

27. The Authority notes that the normal value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case none of the producers and exporters from China PR has filed any market economy treatment (MET) questionnaire and, therefore, the Authority notes that options under para 7 of Annexure 1 to AD rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that the normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. It is noted that the domestic sales price of the subject goods in a market economy third country was not available. However, there are exports of the subject goods from Turkey to the world, including India and the applicants have provided information regarding that. The applicants have also submitted that the European Commission in a recently concluded sunset review investigation against imports of persulphates from China, dated 16th January, 2020, has considered Turkey as an appropriate surrogate country for China PR. After consideration of the volume and the value of exports from Turkey to the third countries including India, it has been found that this methodology can be considered as the basis for determination of the normal value. The Authority has thus considered Turkey as an appropriate third country and the average export price of Turkey to the world, including India, has been considered as the normal value. The normal value so determined is shown in the dumping margin table below.

II. USA**b. Determination of the Normal Value for USA**

28. According to Section 9A (1)(c), the following can form the basis for the determination of normal value in the exporting country.
- a. The price of the like article in the domestic market of the exporting country in the ordinary course of trade,
 - b. Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country,
 - c. The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.
29. As provided under the law, the Authority is required to consider the selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of USA for determining the normal value in USA. The applicants have also made available the re-sale price of the subject goods, along with the documentary evidence, by such related company in USA to which the exports of the subject goods were made. The Authority notes the re-sale price of the subject goods is comparable with the average import price of the subject goods into USA as seen from the World Trade Data. The USA has a dedicated HS code at 10 digit level for all the three types of the subject goods. After examining the submissions of the domestic industry and various interested parties, the normal value in USA has been determined using the price prevailing of the subject goods in USA, after making due adjustments, and such price has been considered as the normal value for the USA. The normal value so determined is shown in the dumping margin table below.

c. Determination of Export Price for China and USA

30. The Authority notes that none of the exporters have furnished information to the Authority in the form and manner prescribed which could be used for determination of the export price and the individual dumping margin. Therefore, the Authority has determined the export price for the producers/exporters in the subject countries on the basis of the DGCI&S transaction wise data. The export price has been adjusted on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Separate weighted average export price to India has been determined for each type of persulphates which is provided in the

dumping margin table below. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from the subject countries so determined is as shown in the dumping margin table below.

F.4 Dumping Margin

31. Considering the normal values and the export prices determined as above, the dumping margin for the producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below. Since there is no export of PPS in the POI, the dumping margin has not been calculated for the same. The dumping margin of the imports from the subject countries is not only above de minimis level, but also substantial.

Dumping Margin Table

In case of USA

Particulars	APS	SPS	Weighted Average
	USD/MT		USD/MT
Normal Value	***	***	***
Net Export Price	***	***	***
Dumping Margin	***	***	***
Dumping Margin %	***	***	***
Dumping Margin % (Range)	130-140	60-70	80-90
Import Volume (MT)	429	578	1,007

In case of China PR

Particulars	APS	SPS	Weighted Average
	USD/MT		USD/MT
Normal Value	***	***	***
Net Export Price	***	***	***
Dumping Margin	***	***	***
Dumping Margin %	***	***	***
Dumping Margin % (Range)	60-70	10-20	60-70
Import Volume (MT)	1,649	60	1,709

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Methodology for Injury Determination and Examination of Causal Link

32. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of the factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the

like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

G.1. Submissions made by the other interested parties

33. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. The rebuttal of the petitioners that injury formats were provided on cumulative basis which implies demand for cumulative assessment is frivolous, because a claim for cumulative assessment should be justified by citing proper grounds and merely providing a combined proforma of injury will not satisfy the requirements.
- ii. The petitioners did not make any express claims to justify cumulative assessment in the petition.
- iii. Import data shows that the price of PUC from USA was higher by 50.88% compared to China PR and the volume of imports from China PR was higher by 69.71% compared to USA. The difference in price and volume from China PR and USA is substantial. Import price and volume from China PR shows that claimed injury could be on account of such imports and the same should not be attributed to fair and high-priced import from USA.
- iv. The comparison of volume and landed price from China PR and USA clearly show that the two moved in different directions and cumulating the two thereafter is illogical.
- v. APS import from USA was at negative undercutting level, there is a huge difference between undercutting in SPS from USA and China PR. There is even a significant difference is undercutting at PUC level from USA and China PR.
- vi. Importers preferred USA material over China PR and the Indian product due to quality issues at the end-user level and price was not the concern. The conditions of competition of imports from subject countries and domestic sales were not the same for imports from USA and other products.
- vii. The imports from China PR increased considerably after expiry of the duty with sharp reduction in price during the current POI, whereas imports from USA declined by about 307 MT in the POI over the 2018-19 period and the price during the POI was clearly comparable to previous years. Thus, exporters from USA and China PR should not be placed on the same pedestal.
- viii. The examination of dumping and injury separately for subject countries shall not affect the legitimate interest of the petitioners in any manner.
- ix. The admission of the petitioners that they are undercutting the price in USA market by exporting the subject goods to USA at a price lower than prevailing price in USA as a retaliatory measure shows that the DI wants the duty in Indian market to engage in such practices to expand in foreign markets, which is not the purpose of ADD investigation. The fact that the petitioners can afford to engage in such trade practices in USA, shows that the claim of dumping and injury made by the petitioners is merely intended to use the ADD for other expansionist purposes.
- x. The facts clearly show that the domestic industry did not suffer any material injury on account of import of subject goods from USA.
- xi. The imports after expiry of duty increased substantially from China PR and imports from USA declined significantly which demolishes the claim of the petitioner that expiry of duty on USA has been a cause of continued imports from USA.
- xii. The decline in profits and ROCE during the POI is attributable to significant increase in interest and depreciation costs of the petitioners and the fall in profit cannot be linked to imports from USA. Such increase in cost is on account of the fresh capacity additions during POI and also during the immediate previous years.

- xiii. The cash profits of the company increased from 100 to 106 points in the POI indicating the healthy situation of the DI which also shows that the claimed decline in profits have been on account of increase in cost only.
- xiv. Production, sales, capacity utilization even after multiple capacity additions etc. were at the highest level during the POI.
- xv. The domestic industry is expanding its business on all fronts which is evident from the increase in capacity and also exports coincided with very robust performance on profitability parameters.
- xvi. There is no causal link between the injury claimed and the alleged dumped imports from USA.
- xvii. All 3 materials (APS, SPS & PPS) manufactured by UI VR Persulphates have really short life span, subjecting it to drastic quality changes while stocking.
- xviii. Due to the superior quality, the importers prefer USA imports over locally manufactured goods as their customers need to use less amount of imported material than locally manufactured material in their processing.
- xix. Petitioners are trying to implicate USA as it is apparent that UI has significant production facilities in China PR and the company wants to get ADD on USA also in India to block imports from USA into India.
- xx. 22% ROCE on fresh investments should not be considered while determining NIP, and a reasonable alternative should be considered in case of such fresh investments to avoid unreasonable NIP and return levels.

G.2 Submissions made by the domestic industry

34. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link:

- i. All the parameters and factors of the data presented in the application were explained cumulatively implying that the imports from the subject countries and their impact have been addressed cumulatively.
- ii. The application does not require to contain analysis of the data being presented, and merely providing data in support of application is sufficient. This view was discussed by the Panel in Mexico – Corn Syrup and Thailand – H-beams. Further, there is no such rule that the domestic industry ought to make every claim in writing.
- iii. The argument of the other interested parties that this case is not fit for cumulative assessment as import volume of China is higher than USA and the import price of China is lower than USA, is misleading since the same is based on weighted average price comparison.
- iv. There is insignificant price difference between Chinese and US SPS, while there is a significant price difference in APS. The import volumes increased significantly from China as compared to USA only because the Chinese prices are lower than the US prices.
- v. The interested parties confirmed that they were concerned only with SPS and, therefore, cannot assist the Authority on the inter-se competition between the Chinese and US product in APS. The price difference between US and China has significantly declined in the recent period, thus pointing towards inter-se competition.
- vi. The claim of the other interested parties that volume and landed price from China PR and USA have not moved in different directions is factually incorrect. USA manufacturer Peroxychem is exporting SPS at a CIF price of ***/pmt whereas the Chinese manufacturer is exporting the same grade at a CIF price \$***/pmt. The freight cost of USA is thrice than China, i.e., ***/pmt whereas the freight cost from China is \$***. Thus, effectively, the ex-factory price from USA is much lower than China, while the landed price is quite comparable. The same could be verified from the importers also.

- vii. The domestic industry had little or no deterioration in their performance of PPS as there were no imports of PPS but due to the significant imports of APS and SPS, there was significant deterioration in the performance of the domestic industry in APS and SPS. Resultantly, the profitability of APS declined significantly and profitability of SPS went into negative.
- viii. Publicly available information confirms the availability of significant capacities with the subject countries, and they are exporting the subject goods to India at much dumped price.
- ix. Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices, its market share is stagnant and in fact has slightly declined in the POI, whereas demand for the subject goods has increased significantly.
- x. Imports from the subject countries increased till 2017-18 and declined slightly in 2018-19, probably because the exporters knew about the initiation of Sunset Review investigation. It again increased significantly in the POI which shows the effect of cessation of anti-dumping duty.
- xi. Demand for the subject goods increased till 2017-18 and declined in 2018-19 and increased thereafter in the POI. The applicants increased capacity in line with increase in demand. However, the increase in imports were way higher than increase in demand.
- xii. Increase in cost of sale is more than increase in selling price. Thus, imports have suppressing effect on the domestic price in the POI.
- xiii. Subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting for subject goods as a whole as well as for APS and SPS from each subject country is positive and significant.
- xiv. Imports from both the subject countries increased significantly post cessation of anti-dumping duty, and imports from USA were always significant, even when the duty was in place. With such mammoth capacity, much higher domestic prices and availability of electricity at a very cheap rate, USA was able to absorb the anti-dumping duty and continued exporting the subject goods during the injury period as well as the POI.
- xv. USA was able to export the subject goods constantly because they were always and constantly undercutting the domestic price, even after payment of antidumping duty. Thus, the bragging of the importers that USA imports are preferred because of quality is a hoax.
- xvi. USA has restrained Chinese products to enter US market at unfair price but that does not change the fact that USA too has significant capacities like China, and both countries are exporting subject countries to India at dumped prices.
- xvii. The market shares of the domestic industry declined in 2017-18 and increased thereafter in 2018-19 and declined slightly in the POI, while the share of other Indian producers declined significantly in the POI.
- xviii. The domestic industry has not been able to increase its market share due to the presence of significant volume of dumped imports in the market, despite compromising on selling prices.
- xix. Market share of the subject countries increased significantly throughout the injury period. It can be concluded from the market share of other countries that the subject countries have eliminated all the other fair priced imports from the market and now Indian customers are at the mercy of dumped imports from the subject countries.
- xx. The inventories of the domestic industry increased significantly in 2018-19 and then in the POI, thus showing the vulnerability of the domestic industry.
- xxi. The profits of both APS and SPS declined drastically in the POI, and the profits of PPS declined in 2017-18 and thereafter increased because there were no imports of PPS in the POI. This shows a direct link between increase in imports and declined in profitability of the domestic industry.

- xxii. The domestic industry has not been able to increase its prices despite the increase in cost and it was forced to align its prices with the import prices, which decline in the present POI.
- xxiii. The import prices from the subject countries have declined significantly in the POI which forced the domestic industry not to increase their selling price.
- xxiv. Increase in interest and depreciation cost does not break the causal link between the dumped imports and consequent injury to the domestic industry.
- xxv. Growth in price parameters such as profit, cash profit, PBIT and return on capital employed shows negative trend.
- xxvi. The domestic industry is suffering material injury due to the dumped imports from the subject countries.
- xxvii. In addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. This was also underlined by the Panel in EC – Bed Linen, which stated that there is no requirement that each injury factor, individually must be indicative of injury. Thus, increase in certain parameters should not be seen in isolation.
- xxviii. The exports of the subject goods from China PR have been subject to anti-dumping duties in the US and EU since 1997 and 2007 respectively. USITC in its 4th expedited review issued final determination in August, 2019 issued continuing duty of 119% on subject goods from China PR. The European Commission also in its recently concluded expiry review dated 16th January, 2020 extended the anti-dumping duty against Chinese imports ranging from 24%–71.8%. Further, the European Commission also initiated an anti-circumvention investigation against a Chinese exporter.
- xxix. The prices prevailing in US and EU markets are 50%-100% higher than the prices prevailing in India. It is a mere bogey that the consumers will suffer because of the anti-dumping duty.
- xxx. Indian industry is still recovering from the ill-effect of Covid, whereas the Chinese industry has already recovered and is running in full capacity, apart from the significant excess capacity that China holds for persulphates.
- xxxi. Since there are existing trade barriers imposed in major markets like EU and USA, and increasing demand for subject goods in India, it is imminent that China will divert its exports to India in an intensified manner.
- xxxii. The capacity utilization rate of persulphate producers in China is about 45.5 percent and that the excess capacity is 221,052 metric tons.
- xxxiii. Non-participation by the exporters/producers indicate that they do not consider significant adverse impact on them as a result of the present investigation.
- xxxiv. The subject countries are taking undue advantage of the increasing demand in India by exporting the subject goods at dumped price to capture the entire Indian market and eliminate the domestic industry from the list of limited producers available across the globe.
- xxxv. The Indian electronics market is expected to reach USD 400 billion by 2025. India is expected to become the fifth-largest consumer electronics and appliances industry in the world by 2025. The polymer and electronics industry are likely to prove to be the major revenue generator for persulfates market during the review period 2018-2023 owing to the growing preference for polymers over metals and the rising consumer appliances demand across the globe.
- xxxvi. The consumer industry is not concerned about imposition of anti-dumping duty, and they are well aware that imposition of ADD will not impact them adversely as is evident from the fact that only one user has opposed the imposition of anti-dumping duty.

- xxxvii. The responses filed by M/s Jay Chemical industries Pvt Ltd, M/s Rashmi Trading Company, M/s Sagar Speciality Chemicals Pvt Ltd do not mention the impact of imposition of anti-dumping duty.
- xxxviii. The contention that the imposition of anti-dumping duties would lead to increase in prices in the domestic industry and will have adverse effect on the users should be outrightly rejected as it is tantamount to saying that the parties should be allowed to continue access to unfairly priced product and the user industry cannot survive without access to unfairly priced raw materials.
- xxxix. Since Chem Intel did not file importer questionnaire response, authorization and intent to participate, and no justification was given for the non-filing of the response by this importer, any submission made on their behalf should be rejected.

G.3 Examination by the Authority

35. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and examined various parameters in accordance with the relevant Rules and Annexure III.

i. Cumulative Assessment

36. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
37. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
38. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
39. Rule 11 of AD Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”
40. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc., have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

41. In consideration of the various submissions made by the interested parties with regard to injury and causal link, the Authority proceeds to examine the injury to the domestic industry. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties in accordance with the relevant Anti-Dumping Rules and Annexure II. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

ii. Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

42. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of the Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all the countries. For the purpose of the present injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased over the injury period as can be shown in the table below:

Demand	MT	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	110	145
Sales of Other Indian Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	104	58
Subject country-Imports	MT	1,424	1,956	1,699	2,716
Trend	Indexed	100	137	119	191
Other Countries-Imports	MT	230	469	47	90
Trend	Indexed	100	204	20	39
Total demand/consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	108	144

43. It is seen that demand for the subject goods increased in 2017-18 and declined in 2018-19 and increased again in the POI.

b. Import Volumes and Share of the Subject Countries

44. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods and the share of the dumped imports during injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Import Volume					
China	MT	477	872	385	1,709
Trend	Indexed	100	183	81	358
USA	MT	947	1,084	1,314	1,007
Trend	Indexed	100	114	139	106
Subject Countries	MT	1,424	1,956	1,699	2,716
Trend	Indexed	100	137	119	191
Other countries	MT	230	469	47	90
Trend	Indexed	100	204	20	39
Total Imports	MT	1,654	2,425	1,746	2,806
Trend	Indexed	100	147	106	170

45. It is seen that imports of the subject goods from the subject countries have increased by 91% since the base year and 61% in the POI as compared to the previous year. It is noted that the antidumping duties were in place on the subject countries till May, 2019. Thus, even when the anti-dumping duties were in place, the imports from the subject countries in the POI had increased as compared to the base year.

c. Subject Countries imports in Relative terms

46. Imports in relative terms show as follows:

Subject imports in relation to	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	114	152
Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	113	133

47. It is seen that the imports in relation to production increased till 2017-18 and slightly declined in 2018-19 and increased significantly in the POI. Whereas imports in relation to consumption have increased throughout the injury period. Thus, imports have increased in both absolute and relative terms.

iii. Price Effect of the dumped imports on the domestic industry

48. Regarding the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

49. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

Product: Persulphates- China PR					
Year	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Import volume	MT	477	872	385	1,709
Import value	Rs.Laks	291	528	234	875
Assessable value	Rs. /Kg	61	61	61	51
Custom duty	%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
Custom duty amount	Rs. /Kg	5	5	5	4
Cess/SWC	%	3%	3%	10%	10%
Cess/SWC amount	Rs. /Kg	0	0	0	0
Landed value	Rs. /Kg	66	65	66	55.42
Trend	Indexed	100	98	100	84
Selling price	Rs. /Kg	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	98	97	98
Price undercutting	Rs. /Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	30-40	30-40	30-40	40-50

Product: Persulphates- USA

Year	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Import volume	MT	947	1,084	1,314	1,007
Import value	Rs. Laks	765	877	1,145	804
Assessable value	Rs. /Kg	81	81	87	80
Custom duty	%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
Custom duty amount	Rs. /Kg	6	6	7	6
Cess/SWC	%	3%	3%	10%	10%
Cess/SWC amount	Rs. /Kg	0	0	1	1
Landed value	Rs. /Kg	87	87	94	86
Trend	Indexed	100	100	108	99
Selling price	Rs. /Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	97	98
Price undercutting	Rs. /Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	10-20	0-10	20-30

50. It is seen that the landed values from the subject countries, cumulatively and individually, have been below the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices. The domestic industry has contended that imports from USA were significant during the injury period as well because they were able to absorb the existing anti-dumping duties. It was contended that the imports from USA were undercutting the domestic industry prices even after paying anti-dumping duty.

b. Price suppression and depression

51. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. The factual position is as follows:

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of production	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	105	113
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	97	98

52. It is seen that the cost of production has increased over the injury period, whereas the selling price has declined over the injury period. Year on year movement shows that the cost of production declined in 2017-18 when the selling price also declined. Thereafter the cost of production increased by almost 33% in the POI. However, the selling price remained at the same level. It has been contended that the movement of cost of production and selling price type wise shows clear impact of dumped imports as there is no price suppression or depression in the POI for PPS wherein imports are not entering the domestic market. However, price depression is clearly visible for APS and SPS.

H. Economic Parameters of the domestic industry

53. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and submissions made.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

54. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	116	138
Production PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	127	154
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	109	112
Sales Volume-Domestic	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	110	145

55. It is seen that

- The domestic industry enhanced its capacity throughout the injury period.
- Production and capacity utilisation of the domestic industry have increased throughout the injury period.
- Sales of the domestic industry increased till 2017-18, and increased thereafter in the POI. The sales of the domestic industry have not increased to the extent of increase in production and demand in view of increase in imports in the POI.

b. Profitability, Return on investment and Cash profits

56. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profits	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	77	61
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	156	88	106
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	161	89	116
RoCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	44	50

57. It is seen that:

- i. Profitability of the domestic industry increased in 2017-18 and declined thereafter significantly in 2018-19 and the POI.
- ii. Cash profit, PBIT and ROI have increased till 2017-18 and declined in 2018-19 with a marginal increase in the POI. The domestic industry was earning healthy returns in the base year and 2016-17 but the same declined significantly over the injury period.
- iii. The domestic industry contended that profits of both APS and SPS also declined drastically in the POI, and the profits of PPS declined in 2017-18 and thereafter increased because there are no imports of PPS in the POI. This shows a direct link between increase in imports and decline in profitability of the domestic industry. The domestic industry has not been able to increase its prices despite the increase in cost and is forced to align its prices with the import prices, which declined in the present POI.

c. Market Share in Demand

58. Market share of the domestic industry is shown in the table below:

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	102	100
Sales of Other Indian Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	100	44
Subject countries-Imports	%	***	***	***	***
Other Countries-Imports	%	***	***	***	***
Total	%	100	100	100	100

59. It is seen that:

- i. Market share of the domestic industry has remained at similar levels over the injury period with some decline in the POI as compared to the previous year. Market share of other Indian producers have also declined in the POI.
- ii. Market share of the subject countries have increased significantly in the POI. Market share of the other countries has declined.
- iii. It was contended by the domestic industry that despite compromising on selling prices and anti-dumping duty in place, the domestic industry has not been able to increase its market share due to presence of significant volume of dumped imports in the market which have captured the potential market share of the domestic industry and actual market share of the other producers and other countries.

d. Employment and wages

60. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	116	129
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	641	779	902

61. It is seen that employment and wages of the domestic industry increased throughout the injury period.

e. Inventories

62. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Stock (Volume)	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	193	455	509

63. It is seen that inventories with the domestic industry increased significantly in 2018-19 and the POI. The domestic industry has not been able to sell the subject goods even though there was increase in demand, capacity and production.

f. Ability to raise capital

64. The domestic industry has recently made an investment. Thus, the ability to raise capital has not been impacted so far. Should the domestic industry be prevented from utilising such expanded capacity, its ability to raise capital may jeopardise.

g. Factors affecting domestic prices

65. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting. The price undercutting has led to price suppression in the Indian market. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices.

I. Magnitude of Injury and Injury margin

66. Non-Injurious Price for the domestic industry has been determined on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price of each PCN from each of the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as per procedure prescribed in Annexure-III. The non-injurious price for each PCN so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries for comparable PCN to determine the injury margin as follows:

Injury Margin USA	APS	SPS	Average
Import Volume (MT)	429	578	1,007
	USD/MT		USD/MT
NIP	***	***	***
Landed Value	1,001	1,369	1,212
Injury Margin	(***)	***	***

Injury Margin %	(***)	***	***
Injury Margin % (Range)	(20-30)	20-30	0-10
Injury Margin China PR	APS	SPS	Average
Import Volume (MT)	1,649	60	1,709
	USD/MT		USD/MT
NIP	***	***	***
Landed Value	754	1,315	774
Injury Margin	***	***	***
Injury Margin %	***	***	***
Injury Margin % (Range)	0-10	20-30	0-10

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

67. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

68. Imports from the other countries are either low in volume or are at higher price than the import prices from the subject countries.

b. Export Performance

69. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

c. Development of Technology

70. There are no known material developments in technology over the injury period. Changes in the technology could not have caused claimed injury to the domestic industry.

d. Performance of other products of the company

71. The Authority has considered performance of the domestic industry only in respect of product under consideration. The injury claimed to the domestic industry is only in respect of the subject goods.

e. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

72. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

f. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

73. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it is the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand or changes in pattern of consumption.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS**K.1 Submissions made by the other interested parties**

74. Post disclosure comments made by the other interested parties are as follows:

- a) PPS has not been imported into India from any of the subject countries during the POI. There are separate dumping and injury margin determined for SPS and APS, no such determination has been made for PPS in absence of imports. The inclusion of PPS within the product scope means that the duty determined for APS and SPS shall be applied on PPS as well which cannot be a justifiable approach. The Authority may reconsider its proposal to inclusion of PPS in the scope of the PUC.
- b) The significant dumping margin for the USA is a result of unsubstantiated method of normal value and this cannot be considered real.
- c) The current injury margin requires thorough examination as this is in the same range for China and USA. This cannot be true as prices of SPS and APS from USA are higher than the Chinese prices by 36%.
- d) In view of separate import trends from USA and China, imports from these countries are incomparable and should be examined separately.
- e) There are no data to support increase or decrease in profitability trend for the applicants. The overall volume and price parameters of the domestic industry shows robust situation. The minor fall in profits during the POI was on account of very high profits in the previous year.
- f) Owing to difference in prices between APS and SPS, the ADD should also be recommended on product type basis as there is no basis for determining weighted average margins/duty liability. Type wise/PCN wise ADD have been recommended in various cases like Jute products.
- g) There is absence of causal link between imports from the USA and consequent injury to the domestic industry.

K.2 Submissions made by the domestic industry

75. Post disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

- a. There is no relationship and no control by the alleged related companies over the applicant company. The alleged related companies have certified that no exports were made during the POI by these companies. It would be seen from the letters filed earlier that:
 - i. United Initiators Hefei Co. Ltd., China, is 100% subsidiary of UI Gmbh. They are involved in manufacturing and exporting the subject goods from China.
 - ii. United Initiators Hefei Co. Ltd., China, has not exported the subject goods to India during the period of investigation.
 - iii. None of the other related companies of UI Gmbh is involved in manufacturing and exporting the subject goods from China.
- b. United Initiator Inc, USA is not involved in manufacturing the subject goods in USA. It is involved in trading of persulfates in the domestic market of USA. United Initiator Inc, USA has not exported persulfates to India during the period of investigation. There is a threat of material injury in view of increased imports from subject countries in the proposed POI, excess production capacity with producers/exporters in the subject countries, Indian market being attractive for exporters, third country measures on subject goods from subject countries and quick recovery of China from COVID 19 in comparison to the rest of the world.
- c. The price undercutting and injury margin should be determined only considering those transactions whose landed price of imports is below the selling and non-injurious price of the domestic industry.
- d. There is no requirement as per Article 3.2 of Anti-Dumping Agreement to establish one single margin of undercutting on the basis of an examination of every transaction involving the product under consideration. The domestic industry has also made reference to CESTAT's decision in *Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority* which allowed considering transactions below NIP to calculate injury margin.

- e. The import price has declined significantly within the POI and have declined further after the POI. The adequate duty to protect the domestic industry from unfair trade practice should be based on current prevailing prices. The duty level on the basis of average landed price for the POI will not be sufficient enough to remove the injury to the domestic industry on account of dumped imports.
- f. Only one user participated in the investigation and has failed to provide any evidence to show adverse impact of dumping. The overall impact of anti-dumping duty, if imposed, on user industry will be miniscule. The subject goods are primarily used in textile and chemical industries. Depending on the formulation consumption pattern for APS is 0.5% to 1.5% of the total costs as its only use is as an oxidizing agent irrespective of the industry. Similarly, the consumption pattern for SPS is around 1.3% to 1.65%. Thus, a batch of 1000kg end product will roughly consume only 0.5% to 1.75%. The ultimate impact will be miniscule.
- g. The normal value in USA should be considered as the price at which the subject goods are being sold in US market. The price for normal value will be taken as consumption price, not the price at which it was sold by the applicant company to its affiliate company. As noted by the Authority the resale price is comparable to the import price into USA which is also the consumption price of subject goods and the Authority has rightfully considered the same.

K.3 Examination by the Authority

76. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:
- a. As regards the contention that PPS is not being imported but it is still included in the product scope, it is reiterated that SPS, APS and PPS are all forms of one product under consideration. The Authority further notes that the import of each type of the product under consideration within the POI is not a mandatory requirement under the law. So long as a product type falls within the definition and scope of the product under consideration, the same is required to be included within the scope of the product under consideration. In any case, there are imports of the product type over the injury period. There were imports of this type even in the previous investigations. The Authority also notes that the three types of Persulphates serve the same general purpose. The consumers normally do not switch one type with the other type in a short run. However, there are several applications where all three types of Persulphates can be used interchangeably. Also, the producers can produce all the three types interchangeably. Based on the past investigations undertaken by the Authority and the decision by other jurisdiction, APS, PPS and SPS are types of one product under consideration and cannot be seen in isolation for the import purposes. Having regard to the fungibility of the production process and the product within APS, SPS and PPS and the fact that there are imports of PPS during the injury period, the Authority finds it inappropriate to exclude PPS from the scope of the product under consideration.
 - b. As regards the argument that the dumping margin for USA is the result of unsubstantiated method of the normal value, it is clarified that the methodology has been adequately explained. It is clarified that since none of the producers from USA has responded, the Authority has examined the evidence before the Authority in the form of (a) the exports made by the applicant industry to USA and (b) the resale price of one of the applicant companies. The information of the resale price of the trader in USA was made available and (c) the imports into USA as the price prevailing in USA, which has information for each type of the product concerned. After examining this evidence, the Authority found it appropriate to consider the resale price of the subject goods in the domestic market of USA which is comparable with the import price of the subject goods in USA.
 - c. As regards the argument that the methodology for determining the injury margin appears to be incorrect and weighted average margins should be considered, it is clarified that the weighted average injury margins have been considered for the determination of average injury margin.
 - d. As regards the argument that the cumulative assessment cannot be done in the present case and that the imports from USA are not causing injury, it is noted that all the requirements of the cumulative assessment are present and upon satisfaction of such conditions, the Authority has found it

appropriate to cumulate injury. Further, as regards the argument that the imports from USA have declined in the POI, it is noted that the imports from USA are significantly high in the POI. Even though the volume shows some decline in the POI from the previous year, the import prices have declined significantly from USA in the POI when the costs of the domestic industry has increased. The imports from USA are significant in absolute and relative terms. The dumping margin, the injury margin and the price undercutting are positive with respect to the subject goods coming from USA. Thus, the imports from USA along with the imports from China have caused injury to the domestic industry.

- e. The share of APS and SPS imports is materially different in the case of China PR and USA. Whereas the imports of SPS from China PR constitute only ***% of the total imports of the PUC from China PR, the share of SPS in the case of USA is ***% (para 65 above). Further, there is significant price difference between the landed price of SPS and APS, as is evident from table at para 65 above. In view of the significant difference in the prices, the Authority has first determined the injury margin separately for APS and SPS; and thereafter has determined the weighted average on the basis of associated import volumes. It is seen that injury margin in the case of China PR are higher than the injury margin in case of USA, both for SPS and APS. It is also seen that the import price of SPS from USA is higher than China PR by only 4%. The interested parties have incorrectly compared the weighted average prices.

L. INDIAN INDUSTRY INTERESTS AND OTHER ISSUES

77. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
78. The Authority considered whether imposition of the ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of the information on record and the interests of the various parties, including domestic industry, the importers and the consumers of the product.
79. The Authority issued the gazette notification inviting views from all interested parties, including the importers, the consumers and the other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.
80. Two importers and one user, namely, M/s. Jay Chemical Industries Pvt. Ltd. (User); M/s. Rashmi Trading Company and M/s. Sagar Speciality Chemicals Pvt Ltd have participated and filed questionnaire responses. However, the information or submission relevant to substantiate the adverse impact on users has not been provided. It has been argued that the duties will lead to increase in price of the product leading to adversities on the user. However, even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of the ADD and elaborate how the imposition of the ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of the ADD on the user industry with verifiable information. Further, the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is meagre.

81. The Authority notes that the product is under free category and, therefore, can be freely imported from the various countries. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It is noted that there are various global players in the production of the subject goods. The investigations have been conducted in the past by against the imports of the subject goods originating in Japan, Turkey and Taiwan India which show that these are the countries where goods are being produced and from where were being exported to India. The EU and USA are also producers of the subject goods. Thus, there are alternate source of supply of the subject goods. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would neither affect the availability of the product to the consumers nor create monopoly.
82. The EU and USA have also investigated the imports of the product under consideration into USA and EU respectively from China PR. The EU and USA have imposed the duties on the said imports on finding that the imports are causing material injury to their domestic industry. The duties have been in force against China since the 24 years and 14 years respectively. The quantum of duties levied by the US and EU Authorities is 119% by USA and 24.5-71.8% by EU respectively, which indicates the level of dumping that China is resorting to in other countries.
83. It is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of the subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry has submitted that the cost of product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. The subject goods are primarily used in textile and chemical industries. Depending on the formulation, consumption pattern for APS is 0.5% to 1.5% of the total costs as its only use is as an oxidizing agent irrespective of the industry. Similarly, the consumption pattern for SPS is around 1.3% to 1.65%. Thus, a batch of 1000kg end product will roughly consume only 0.5% to 1.75%. The ultimate impact will be miniscule.
84. It is, thus, noted that while the interested parties have not established possible adverse impact of proposed ADD on the user industry with verifiable information, even if it is considered that the imposition of the ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of the imposition of the anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by the dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

85. After examining the submissions made by the interested parties and the issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - a. The applicant constitutes the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product produced by the domestic industry is like article to the PUC imported from the subject countries. PPS is a form of product under consideration and should be included in the product scope.
 - c. Considering the normal value and the export price for the subject goods, type wise dumping margin for the subject goods from the subject countries has been determined, and the margins are significant.
 - d. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry shows that the volume of the dumped imports from the subject countries has increased in both absolute and relative terms. The volume of the subject goods has increased by more than 100% in the POI on absolute terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry, and the margin of price undercutting is around 15-25 percent for USA and around 40-50 percent for China PR. It is also noted that the imports of subject goods from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The market share of domestic industry has been in the similar range, despite the capacity increase and increase in the demand. The performance of the domestic industry has

deteriorated in respect of the profits and the return on the capital employed. The profitability has declined steeply in the POI. The cash profit, PBIT and ROI have increased till 2017-18 and declined in 2018-19 with a marginal increase in the POI.

- e. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
 - f. Despite providing all formats for users to quantify the impact of the ADD and elaborate on how imposition of the ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant quantified information. The interested parties have not established the impact of the ADD on the user industry with verifiable information. Non-imposition of the anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned and the fact that the impact of the antidumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.
86. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers and the other interested parties to provide the information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into the dumping, injury and the causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and the consequential injury. Therefore, the Authority recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
87. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of the dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority, therefore, considers it necessary to recommend the imposition of the definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in the column (7) on all the imports of the subject goods described at Column (3) of the duty table, originating in or exported from China PR and USA, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1.	2833 40 and 283340 00	Ammonium Persulphates (APS)	China PR	Any country including China PR	Any producer	19	MT	USD
2.	2833 40 and 283340 00	Sodium Persulphates (SPS)	China PR	Any country including China PR	Any producer	201	MT	USD
3.	2833 40 and 283340 00	Potassium Persulphates (PPS)	China PR	Any country including China PR	Any producer	32	MT	USD
4.	2833 40 and 283340 00	Ammonium Persulphates (APS)	Any country including China PR	China PR	Any producer	19	MT	USD
5.	2833 40 and 283340 00	Sodium Persulphates (SPS)	Any country including China PR	China PR	Any producer	201	MT	USD
6.	2833 40 and 283340 00	Potassium Persulphates (PPS)	Any country including China PR	China PR	Any producer	32	MT	USD

7.	2833 40 and 283340 00	Ammonium Persulphates (APS)	USA	Any country including USA	Any producer	NIL	MT	USD
8.	2833 40 and 283340 00	Sodium Persulphates (SPS)	USA	Any country including USA	Any producer	344	MT	USD
9.	2833 40 and 283340 00	Potassium Persulphates (PPS)	USA	Any country including USA	Any producer	100	MT	USD
10.	2833 40 and 283340 00	Ammonium Persulphates (APS)	Any country including USA	USA	Any producer	NIL	MT	USD
11.	2833 40 and 283340 00	Sodium Persulphates (SPS)	Any country including USA	USA	Any producer	344	MT	USD
12.	2833 40 and 283340 00	Potassium Persulphates (PPS)	Any country including USA	USA	Any producer	100	MT	USD

N. FURTHER PROCEDURE

88. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority